नमो impact

वसुधैव कुटुम्बकम्

परिकल्पना एवं निर्माण

अतुल सिंघल

नमो impact

वसुधैव कुटुम्बकम्

परिकल्पना एवं निर्माण

अतुल सिंघल

प्रस्तावना

प्रो. जगदीश मुखी

पूर्व राज्यपाल

ISBN: 9789385830228

नमो Impact

© **अतुल सिंघल**

परिकल्पना एवं निर्माण
अतुल सिंघल
+91 9811460700 / atulsinghal25@gmail.com
संपादन – **श्री पंकज कुमार, श्री उदय कुमार सिंह, श्री नरेंद्र वर्मा**
डिज़ाइन – रौनाज मीडिया प्रा. लि. एवं परवाज़ क्रिएशंस
कानूनी सलाहकार – एडवोकेट **श्री शशांक देव सुधी**
वित्तीय सलाहकार – CA **श्री सतीश गुप्ता**
सोशल मीडिया – www.workafy.com
सामाजिक संस्था – **लाला कुंदन लाल (मंगलौर वाले) सेवा न्यास**
प्रकाशक – स्टैंडर्ड पब्लिशर्स
205, किरण मेंशन, 4834/24 मेन अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली–110002 (भारत)
निर्माता: एटमास मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–5/156, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली (भारत) – 110085

द्वितीय संस्करण – 2024

मूल्य: ₹ 5000/– $ 100/– £ 80/–

इस पुस्तक से संबंधित सर्वाधिकार अतुल सिंघल और एटमास मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास सुरक्षित हैं।
प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना पुस्तक में शामिल किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन नहीं किया जा सकता।

संपादकीय सलाहकार

श्री नरेश बंसल, सांसद राज्यसभा (अध्यक्ष)
स्वामी चिदानंद जी मुनि, परमार्थ निकेतन
प्रो. सुरेश चंद सिंघल, प्रमुख समाजसेवी
श्री विनीत गुप्ता लोहिया, चेयरमैन, नमो इंपैक्ट
श्री जगदीश राय गोयल, प्रमुख समाजसेवी

www.namoimpact.com
www.twitter.com/atulsinghal25?s=08
www.facebook.com/namoimpact?mibextid=ZbWKwL
www.instagram.com/atulsinghal25
www.youtube.com/@namoimpact

माँ को समर्पित

(श्रीमती ऊषा सिंघल)

"मुझे देश के लिए
मरने का मौका नहीं मिला,
लेकिन मुझे देश के लिए
जीने का मौका मिला है।"

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

विषय-सूची

प्रस्तावना — प्रो. जगदीश मुखी — 08

शुभकामना संदेश — स्वामी चिदानंद सरस्वती — 09

शुभकामना संदेश — श्री नरेश बंसल — 10

मेरी बात — अतुल सिंघल — 11

विदेश नीति — डॉ. विजय जौली — 12

जी20 — श्री सुशील सिंघल / श्री एकनाथ ढकाल — 14

ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी — श्री राकेश जैन — 16

विकसित भारत संकल्प यात्रा — श्री आरिफ मोहम्मद खान — 18

भारतीय मुद्रा — श्री बी.डी. नारंग — 20

अंतरिक्ष अभियान — डॉ. अखिलेश गुप्ता — 22

आम आदमी की उड़ान — श्री वी.पी. अग्रवाल — 24

नए भारत की ट्रेन : वंदे भारत — श्री आलोक कंसल — 26

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना — श्री राम चंद्र जांगड़ा — 28

पर्यटन नीति — श्री के.बी. काचरू — 30

लक्षद्वीप की बढ़ती लोकप्रियता — श्री एस.पी. अग्रवाल — 32

विकास का प्रतिमान सुमंगलम — डॉ. बजरंग लाल गुप्ता — 33

5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था — श्री विनीत लोहिया — 34

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग — श्री ठाकुर अनूप सिंह — 36

सेंट्रल विस्टा / इंडिया नहीं भारत — श्री नरेश बंसल — 38

भारत: लोकतंत्र की जननी — श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, श्री सत्यदेव चौधरी — 40

नमामि गंगे — स्वामी चिदानंद जी सरस्वती — 42

पराक्रम दिवस — प्रो. जगदीश मुखी — 44

3 तलाक / यूसीसी — डॉ. नंद किशोर गर्ग — 46

डिजिटल भारत — डॉ. पवन दुग्गल — 48

प्रधानमंत्री जनधन योजना — डॉ. तेजेन्द्र मोहन भसीन — 50

स्वावलंबन से सशक्तिकरण — श्रीमति प्रियंका सिंह रावत / श्रीमति संतोष यादव — 52

नारी शक्ति वंदन अधिनियम — श्रीमती शालीना चतुर्वेदी — 54

एक्ट-ईस्ट नीति — प्रोफेसर कपिल कुमार — 56

असम — श्री जयंत मल्ला बरुआ — 58

मेघालय — श्री एलेग्जेंडर लालू हेक — 59

आत्मनिर्भर भारत — श्री कश्मीरी लाल — 60

राष्ट्रीय शिक्षा नीति — प्रो. मनोज कुमार तिवारी / डॉ. महेश वर्मा — 62

खेलो इंडिया — श्री देवेंद्र झाझरिया / सुश्री बबीता फोगाट — 64

डबल इंजन की सरकार — श्री मनोहर लाल खट्टर — 67

उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश
डॉ. अनिल अग्रवाल
68

छत्तीसगढ़ियों ने नक्सलवाद को नकारा
श्री बृजमोहन अग्रवाल
70

जीएसटी
श्री वी. के. गर्ग
72

नागरिकता संशोधन अधिनियम
न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग
74

धारा 370
श्री मंजूर भट / श्री महबूब अली खान
76

पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है
जनरल ढी.पी. वत्स
79

कोरोना महामारी
श्री अश्विनी चौबे
80

राष्ट्र प्रथम
श्री लक्ष्मी नारायण भाला
82

स्वच्छ भारत अभियान
स्व. डॉ. बिंदेश्वर पाठक
84

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
साध्वी ऋतंभरा जी
86

सशक्त सेना सशक्त भारत
कर्नल टी. पी. त्यागी
88

भारतीय जन औषधि परियोजना
श्री रवि दाधीच
90

आयुष्मान भारत
डॉक्टर (प्रो.) जी. के. रथ
92

श्रीराम मंदिर निर्माण
श्री मिलिंद परांडे
94

रामवन गमन मार्ग
सागर से सरयू तक
96

न्याय व्यवस्था
श्री आदीश अग्रवाल
98

समाज कल्याण नीति
डॉक्टर बी. एम. भारद्वाज
100

अद्वितीय संसदीय कार्य
श्री अर्जुन राम मेघवाल
102

श्रम योगी मानधन योजना
श्री पवन कुमार
104

प्रधानमंत्री आवास योजना
श्री प्रदीप अग्रवाल
106

कृषि नीति एवं कृषि कानून
पद्मश्री कमल सिंह चौहान
108

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
श्री नरेंद्र सिंह तोमर
109

गरीब कल्याण अन्न योजना
श्री कैलाश चौधरी
111

प्रेस की स्वतंत्रता
प्रो. के.जी. सुरेश
112

नोटबंदी
स्व. श्री सुदर्शन जैन
114

स्टार्टअप भारत-स्टैंडअप भारत
श्री मोहित राय गोयल / श्री अरविंद कुमार
116

उज्ज्वला योजना
स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज
119

सबका साथ सबका विकास
आचार्य बालकानंद गिरि जी महाराज
120

भ्रष्टाचार मुक्त भारत
श्री अन्ना हजारे
122

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
डॉ. वल्लभभाई कथीरिया / डॉ. भरत देव मुरारी
124

संस्कृत और संस्कृति
रमेश भाई ओझा / श्री दिनेश कामत
126

हिंदुत्व
जगद् गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती
128

जनजाति कल्याण
श्री अतुल जोग
130

स्मार्ट सिटी मिशन
श्री मनोज परिदा
132

ब्रिटिशकालीन कानूनों से मुक्ति
श्री शशांक देव सुधी
134

आजादी का अमृत महोत्सव
श्री जगदीश राय गोयल / श्री राजेंद्र अग्रवाल
136

मेरी माटी मेरा देश
मेजर जनरल विजय पाल
138

एमएसएमई
स्व. श्री सुदर्शन सरीन
140

प्रस्तावना

प्रो. जगदीश मुखी
पूर्व राज्यपाल, असम एवं नागालैंड

'नमो इंपैक्ट कॉफी टेबल' बुक आपके कर कमलों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन-कल्याणकारी नीतियों पर आधारित यह पुस्तक अतुल सिंघल जी ने अपने चैनल नमो इंपैक्ट में लिए गए साक्षात्कारों के आधार पर तैयार की है। ऐसी पुस्तक आज के समय की आवश्यकता है।

नमो इंपेक्ट में विषय से संबंधित एवं निपुण व्यक्तियों से ही साक्षात्कार किए गये हैं। एक पत्रकार के रूप में अतुल जी ने जो कार्य किया है, निश्चित रूप से वह प्रशंसनीय है। नमो इंपैक्ट पर प्रसारित सभी साक्षात्कारों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का चिंतन झलकता है, जो उनके पारिवारिक संस्कारों का परिणाम है। मैंने 'नमो इंपैक्ट कॉफी टेबल बुक' का ध्यान से अवलोकन किया है। अतुल सिंघल जी की टीम ने इसे तैयार करने में काफी लगन से मेहनत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉफी टेबल बुक आपको भी पसंद आएगी।

(प्रो. जगदीश मुखी)
पूर्व राज्यपाल

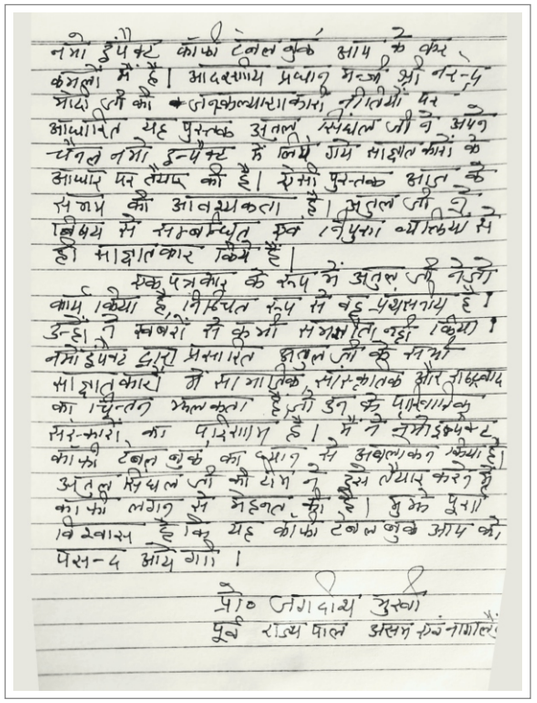

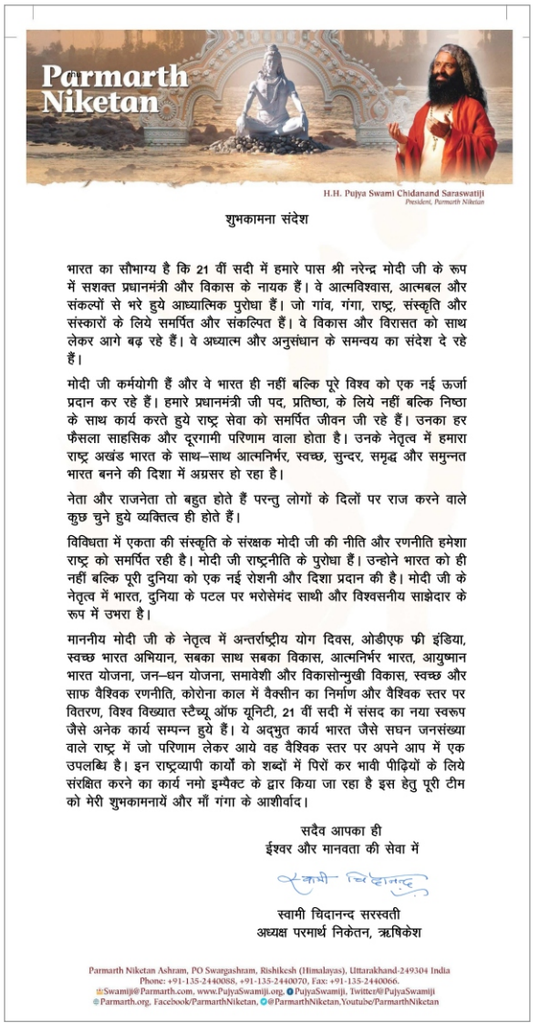

शुभकामना संदेश

भारत का सौभाग्य है कि 21वीं सदी में हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में सशक्त प्रधानमंत्री और विकास का नायक है। वे आत्मविश्वास, आत्मबल और संपल्पों से भरे हुए आध्यात्मिक पुरोधा हैं, जो गांव, गंगा, राष्ट्र, संस्कृति और संस्कारों के लिए समर्पित और संकल्पित हैं। वे विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वे अध्यात्म और अनुसंधान के समन्वय का संदेश दे रहे हैं। मोदी जी कर्म योगी हैं और वे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पद, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र सेवा को समर्पित जीवन जी रहे हैं। उनका हर फैसला साहसिक और दूरगामी परिणाम वाला होता है। उनके नेतृत्व में हमारा राष्ट्र अखंड भारत के साथ-साथ आत्मनिर्भर, स्वच्छ, सुन्दर, समृद्ध और समुन्नत भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। नेता और राजनेता तो बहुत होते हैं,परन्तु लोगों के दिलों पर राज करने वाले कुछ चुने हुए व्यक्तित्व ही होते हैं। विविधता में एकता की संस्कृति के संरक्षक मोदी जी की नीति और रणनीति हमेशा राष्ट्र को समर्पित रही है। मोदी जी राष्ट्रनीति के पुरोधा हैं। उन्होंने भारत को ही नहीं,बल्कि पूरी दुनिया को एक नई रोशनी और दिशा प्रदान की है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत, दुनिया के पटल पर भरोसेमंद साथी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, ओडीएफ फ्री इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत योजना, जन-धन योजना, समावेशी विकास, स्वच्छ और साफ वैश्विक रणनीति, कोरोना काल में वैक्सीन का निर्माण और वैश्विक स्तर पर वितरण, विश्वविख्यात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 21वीं सदी में संसद का नया स्वरूप जैसे अनेक कार्य संपन्न हुए हैं। ये अद्भुत कार्य भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले राष्ट्र में जो परिणाम लेकर आए, वह वैश्विक स्तर पर अपने आप में एक उपलब्धि है। इन राष्ट्रव्यापी कार्यों को शब्दों में पिरोकर भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का कार्य नमो इम्पैक्ट द्वारा किया जा रहा है, इस हेतु पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद।

सदैव आपका ही
ईश्वर और मानवता की सेवा में

स्वामी चिदानंद सरस्वती
अध्यक्ष, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

शुभकामना संदेश

नरेश बंसल

सांसद राज्यसभा एवं सह कोषाध्यक्ष, भाजपा

श्री अतुल सिंघल जी,

एडिटर इन चीफ, नमो इम्पैक्ट टीवी

लोकप्रिय टीवी शो 'नमो इम्पैक्ट', अपने पहले 100 एपिसोड्स पर आधारित एक 'कॉफी टेबल बुक' और 'स्मारिका' का प्रकाशन कर रहा है। भारत सरकार की जन-उपयोगी नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए 'नमो इम्पैक्ट टीवी' का यह प्रयास निश्चित ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।

पिछले नौ वर्ष में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन योजनाओं को सकारात्मक तरीके से जन-जन तक पहुंचाने वाली, तार्किक और व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित यह 'कॉफी टेबल बुक' एक उत्कृष्ट अनुकृति होगी।

'कॉफी टेबल बुक' और 'स्मारिका' के प्रकाशक सहित लेखक व उनकी टीम ने जिस अनूठी शैली का प्रयोग किया है, वह जनकल्याण का आधार बनेगी।

पुस्तक के प्रकाशित होने पर 'नमो इम्पैक्ट टीवी' को निश्चित ही नया बल मिलेगा। इसके प्रकाशन पर सभी को बधाई।

'कॉफी टेबल बुक' और 'स्मारिका' राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से समाज को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त करे, इस दृष्टि से प्रकाशक, लेखक एवं टीम के सभी सदस्यों कोशुभकामनाएं

नरेश बंसल

सांसद (राज्य सभा)

राष्ट्रीय सह कोषाधयक्ष, भाजपा

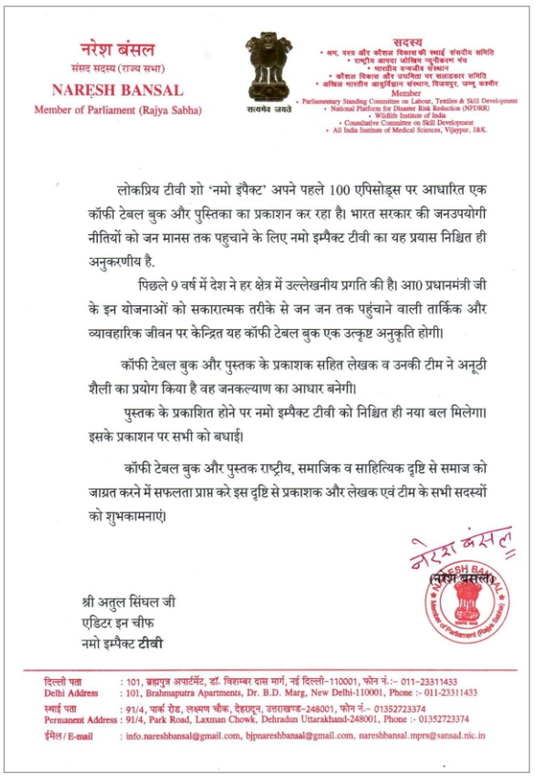

नरेश बंसल
संसद सदस्य (राज्य सभा)
NAREṢH BANSAL
Member of Parliament (Rajya Sabha)

सत्यमेव जयते

सदस्य
• श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थाई संसदीय समिति
• राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच
• भारतीय वन्यजीव संस्थान
• कौशल विकास और उधमिता पर सलाहकार समिति
• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, जम्मू कश्मीर
Member
• Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles & Skill Development
• National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)
• Wildlife Institute of India
• Consultative Committee on Skill Development
• All India Institute of Medical Sciences, Vijaypur, J&K.

लोकप्रिय टीवी शो 'नमो इंपैक्ट' अपने पहले 100 एपिसोड्स पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक और पुस्तिका का प्रकाशन कर रहा है। भारत सरकार की जनउपयोगी नीतियों को जन मानस तक पहुचाने के लिए नमो इम्पैक्ट टीवी का यह प्रयास निश्चित ही अनुकरणीय है.

पिछले 9 वर्ष में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आ0 प्रधानमंत्री जी के इन योजनाओं को सकारात्मक तरीके से जन जन तक पहुंचाने वाली तार्किक और व्यावहारिक जीवन पर केन्द्रित यह कॉफी टेबल बुक एक उत्कृष्ट अनुकृति होगी।

कॉफी टेबल बुक और पुस्तक के प्रकाशक सहित लेखक व उनकी टीम ने अनूठी शैली का प्रयोग किया है वह जनकल्याण का आधार बनेगी।

पुस्तक के प्रकाशित होने पर नमो इम्पैक्ट टीवी को निश्चित ही नया बल मिलेगा। इसके प्रकाशन पर सभी को बधाई।

कॉफी टेबल बुक और पुस्तक राष्ट्रीय, समाजिक व साहित्यिक दृष्टि से समाज को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त करे इस दृष्टि से प्रकाशक और लेखक एवं टीम के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं।

नरेश बंसल
(नरेश बंसल)

श्री अतुल सिंघल जी
एडिटर इन चीफ
नमो इम्पैक्ट टीवी

दिल्ली पता : 101, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, डॉ. विशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं.:- 011-23311433
Delhi Address : 101, Brahmaputra Apartments, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001, Phone :- 011-23311433
स्थाई पता : 91/4, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001, फोन नं.- 01352723374
Permanent Address : 91/4, Park Road, Laxman Chowk, Dehradun Uttarakhand-248001, Phone :- 01352723374
ईमेल / E-mail : info.nareshbansal@gmail.com, bjpnareshbansal@gmail.com, nareshbansal.mprs@sansad.nic.in

मेरी बात

अतुल सिंघल
संपादक

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदरदास मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जन- कल्याणकारी कार्यों से न केवल देश, अपितु दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं। उनके द्वारा घोषित योजनाओं की चर्चा सर्वस्व हो रही है। 2014 में सरकार बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के आमजन को केंद्र में रखते हुए अनेक घोषणाएं की जा रही थीं,जो सुनने में बहुत अच्छी लगती थीं। लोगों को भी काफी उम्मीदें थीं। कुछ ऐसी बातें थीं, जो हमने भी पहली बार सुनी और मन को बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 वर्ष बीतने के बाद मुझे अहसास हुआ कि क्यों ना इन योजनाओं का विश्लेषण किया जाए। मन में ठाना और सीमित संसाधनों के साथ 'नमो इम्पैक्ट" नाम से कार्यक्रम का निर्माण आरंभ हो गया। जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही आभास होता है, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली या नारों का कितना असर देश की आम जनता पर पड़ रहा है, यह देखना उद्देश्य है।

हमारा यह प्रयास रहा कि कार्यक्रम में साक्षात्कार के लिए ऐसे विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए, जो अपने क्षेत्र में स्थापित नाम हों और सरकार उनके सुझावों को गंभीरता से लेती हो। कुल मिलाकर पिछले आठ वर्षों के दौरान यह सफर कभी मंद, तो कभी तेज गति से जारी रहा और वर्ष 2023 के मई महीने में जब प्रधानमंत्री जी के "मन की बात" कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हुए, तो पिता जी ने सुझाव दिया कि मैं भी कुछ ऐसा संकलन करूं, जिससे समाज को लाभ प्राप्त हो सके। अतः मेरे मन-मस्तिष्क में हिंदी की कॉफी टेबल बुक' प्रकाशित करने के विचार ने जन्म लिया। इस उद्देश्य के साथ कि इसे हर वर्ग के हाथों में पहुंचाना है। पुस्तक का थीम सनातन भारतीय परंपरा के अनुसार 'वसुधैव कुटुंबकम' है। इसलिए यह पुस्तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पठन योग्य है।

निःसंदेह कुछ साक्षात्कार आठ वर्ष पुराने हैं और इस बीच स्थितियों-परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। इसलिए हमने अतिथियों के विचारों को आज के परिपेक्ष्य में शामिल करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि इस किताब से पाठकों में जागरुकता आएगी और सरकार को भी नीतिगत फैसले लेने में मदद मिलेगी। यहां यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों योजनाओं का शुभारंभ किया है। सबका समावेश एक पुस्तक में होना असंभव है। इसलिए हमने केवल उन्हीं योजनाओं अथवा कार्यों को सम्मिलित किया है, जिनकी कार्यक्रम "नमो इम्पैक्ट" में चर्चा करके रिकॉर्डिंग की गई है।

प्रत्येक साक्षात्कार के साथ एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पूरा साक्षात्कार सुन सकते हैं। कोई भी कार्य अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। निश्चित रूप से इसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई होंगी। आप सभी के आशीर्वाद से जब अगली पुस्तक प्रकाशित होगी, तब प्राप्त सुझावों का समावेश किया जाएगा।

हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद।

अतुल सिंघल
संपादक

विदेश नीति

वसुधैव कुटुंबकम्

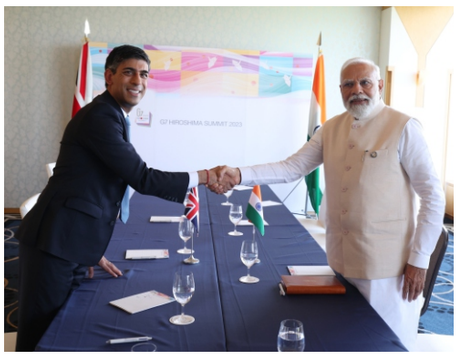

“अब उच्च स्थान पर है भारत”

नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति अब तक की सबसे सफल विदेश नीति मानी जाती है। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने सार्क देशों के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया और कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विदेशों के तूफानी दौरे किए। आज मोदी जी की गिनती विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में होती है। 14 देश उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के साथ सेल्फी और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। कोरोना के समय भारत में छोटे से लेकर बड़े 100 देशों को टीका उपलब्ध कराया। विश्व के करीब करीब सभी देशों में फंसे भारतीयों को एअरलिफ्ट किया।

डॉ. विजय जौली

पूर्व अध्यक्ष, ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी

श्री विजय जौली जी का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वैश्विक जन पटल पर हर एक की आँखों का तारा हैं। ये हर दिल के अंदर बसे हुए हैं। ‘विश्व एक परिवार है’ और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा से प्रेरित मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर अपना संवाद स्थापित किया है। ‘राष्ट्र प्रथम’ की नीति को अपनाते हुए अन्य देशों की आंतरिक राजनीति को भी छुआ है। राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत मोदी जी ने एक नया आयाम, एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से दुनिया का दिल जीता है। अपनी सौम्यता से, अपने काम करने की क्षमता से पहले अपने देश को और फिर विश्व को मंत्रमु कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का आज पूरी दुनिया प्रशंसक है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

कमाल हो गया! जो कहीं नहीं हुआ वह भारत में हो गया। जी-20 सम्मेलन में सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुर में सुर मिलाया। जी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन कर भारत ने सिद्ध कर दिया कि वह न केवल विश्व की सर्वाधिक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है,अपितु वैश्विक राजनीति और कूटनीति में भी सर्वश्रेष्ठ है। सम्मेलन का पहला दिन ही 100 से अधिक उपलब्धियों का गवाह बना। जिसमें दिल्ली घोषणापत्र को पूर्ण सहमति के साथ अपनाना तथा संवेदनशील रूस-यूक्रेन युद्ध पर साझा बयान जारी करना प्रमुख रहा। समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल करना, जैव ईंधन गठबंधन और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा भी प्रमुखता से शामिल रही। जी20 की इस राजनयिक सफलता ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बना दिया। वास्तव में भारत का 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का संदेश सभी प्रतिनिधियों के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित हुआ। भारत की विदेश नीति का ही परिणाम है कि क़तर ने भारत के आठ पूर्व नौसैनिकों को मृत्यदंड की सजा से मुक्त कर दिया।

'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'

"नई दिल्ली घोषणापत्र (नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लरेशन) अपनाने के साथ ही इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति और उत्साह के साथ एकजुट होकर हम एक बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। जी20 के सभी सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री सुशील सिंघल

पूर्व उच्चायुक्त

श्री सुशील सिंघल जी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। श्री सिंघल बताते हैं कि मोदी जी ने अपनी विदेश नीति के द्वारा विश्व के ऐसे छोटे-छोटे देशों में भी भारत की पहुंच बनाई, जहां पिछले 70 साल के दौरान कोई भारतीय मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं गया। आपको विश्वास है कि जल्द ही इसके नतीजे देखने को मिलेंगे और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता दी जाएगी।

श्री एक नाथ ढकाल

सांसद, नेपाल

नेपाल संघीय संसद के सदस्य श्री एक नाथ ढकाल जी का कहना है कि भारत शांति का अग्रदूत है। विश्व शांति के लिए भारत की सहभागिता, भारत की पहल और भारतीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध हो रहा है या दो देशों के बीच विवाद है,वहां मोदी जी विश्व शांति के लिए पहल कर रहे हैं। यही कारण है कि मोदी जी की लोकप्रियता आज चरम पर है। मोदी जी नोबल शांति पुरस्कार के हकदार हैं।

आप अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए।
– जो बाइडेन (अमेरिका के राष्ट्रपति)

मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करता हूँ और भारत जिस प्रकार वैश्विक नेतृत्व कर रहा है, उसे देखना अद्भुत है।
– ऋषि सुनक (इंग्लैंड के प्रधानमंत्री)

प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं।
– एंथोनी अल्बानीज (ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री)

ईमानदारी से कहूँ, तो मैं कभी-कभी भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर मोदी के सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूँ।
– व्लादमीर पुतिन (रूस के राष्ट्रपति)

आप इजराइल में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए।
– बेंजामिन नेतन्याहू (इस्राइल के प्रधानमंत्री)

नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं में उनके सबसे पसंदीदा है।
– जॉर्जिया मेलोनी (इटली की प्रधानमंत्री)

विश्व इतिहास में एक विशाल, भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाने वाला, एक रणनीतिक साझेदार, एक मित्र।
– इमैनुएल मैक्रॉन (फ्रांस के राष्ट्रपति)

मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूँ।
– मोहम्मद बिन सुल्तान (सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस)

मैं 2015 में न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिला था और मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि वह अपने देश को आगे ले जाएंगे।
– अब्देल फतह अल-सीसी (मिस्र के राष्ट्रपति)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया है।

- जुलाई 2023: फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया.
- जून 2023 : मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया.
- मई 2023: पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित हुए.
- मई 2023: फिजी में पीएम मोदी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए.
- मई 2023: पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
- 2021: भूटान ने ड्रुक ग्यालपो से पीएम मोदी को सम्मानित किया.
- 2020: अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया.
- 2019: बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से पीएम मोदी का सम्मान हुआ.
- 2019: मालदीव ने भी ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया.
- 2019: रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया.
- 2019: पीएम मोदी यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवॉर्ड से सम्मानित हुए.
- 2018: ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवॉर्ड से पीएम मोदी सम्मानित हुए.
- 2016: मोदी को अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- 2016: सउदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सऊद से पीएम को नवाजा गया था.

ग्रीन एनर्जी
क्लीन एनर्जी

पर्यावरण के लिए जीवन शैली

भारत ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है और तेजी से गर्म हो रही दुनिया से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित एक 'ग्रीन क्रेडिट पहल' भी शुरू की।

"भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक
स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ रहा है।"
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

“हाथ से हाथ मिलाएं आओ चलें पर्यावरण बचाएं”

“अगर भारत ने 4-जी और 5-जी दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार किया है, तो अपने वन क्षेत्र को भी समान स्तर पर बढ़ाया है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से छुटकारा पाना है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में दुनिया आज बात कर रही है। लेकिन भारत पिछले 4-5 सालों से लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। साल 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए 2 स्तरों पर काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ, हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य बना दिया। पिछले 9 साल में भारत ने ‘हरित और स्वच्छ ऊर्जा’ पर काफी ध्यान केंद्रित किया है।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री राकेश जैन

वरिष्ठ प्रचारक एवं पर्यावरण संरक्षक

श्री राकेश जैन जी उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री रहे हैं। सेवा भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद को भी सुशोभित करने वाले जैन साहब आजकल पर्यावरण गतिविधि के सह संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप ने पर्यावरण के अनुकूल पांच सितारा हरित घरों की परिकल्पना की है, जिसके पांच बिंदु हैं। पांच बिंदुओं में घर का पानी घर में, घर का कूड़ा घर में, पॉलिथीन को समाप्त करना, रसोई की बगिया और परिदा घर बनाना शामिल है। आप लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करके पर्यावरण योद्धा तैयार कर रहे हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर 15 नवंबर 2023 को "विकसित भारत संकल्प यात्रा" का शुभारंभ किया, जो चंद दिनों में ही जनभागीदारी का प्रतीक बन गई। यात्रा का उद्देश्य भी देश की आम जनता से जुड़ना, केंद्र सरकार की योजनाओं की 100 प्रतिशत परिपूर्णता सुनिश्चित करना और उन वंचितों तक पहुंचना था, जो योजनाओं के तहत पात्र तो हैं, परंतु उन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। यह यात्रा देश की लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर जनसामान्य और सरकार के बीच की दूरी को पाटने का तो काम किया ही, भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब सरकार आमजन के दरवाजे तक पहुंची और बताया कि सभी नागरिक सरकारी योजनाओं के हकदार हैं। साथ ही योजनाओं के क्या लाभ है? योजना से कैसे जुड़ें? और कहां पर आवेदन देना है?

प्रधानमंत्री जी ने है ठाना
कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक है पहुंचाना

"विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है, अब उसे लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए जिन गांवो में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसलिए पहले ये यात्रा हमने 26 जनवरी तक सोचा था, लेकिन यात्रा को इतना समर्थन मिला है इसलिए हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री जी का है यह प्रण

कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे जन-जन

"मैं जब गारंटी की बात करता हूं तो मैं अपने को इसके साथ बांधता हूं। यह मुझे सोने नहीं देती, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और अपना सब कुछ देश के लोगों को देने की तरफ ले जाती है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

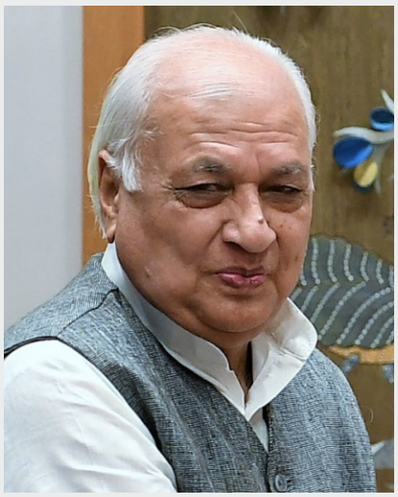

श्री आरिफ मोहम्मद खान

राज्यपाल, केरल

श्री आरिफ मोहम्मद खान विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल और जनहितकारी बताते हैं। आपका कहना है कि इस यात्रा का वास्तविक असर गांव-दर-गांव दिख रहा है। यात्रा के माध्यम से आमजन और जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानियों की संकल्पना के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने यात्रा शुरू करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जयंती का दिन चुना। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाले देशों में से एक है और इसलिए जब जनजातीय समाज के लोग समृद्ध होंगे, तभी भारत विकसित होगा।

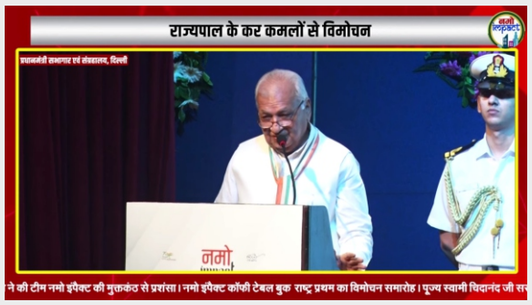

अब भारतीय मुद्रा 'रुपये' में कारोबार दुनिया है तैयार!

भारत सरकार अब 17 से अधिक देशों के साथ अपनी मुद्रा 'रुपये' में व्यापार कर रहा है। इनमें यूके, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बोत्सवाना, इजराइल, फिजी, ओमान, जर्मनी, केन्या, गुयाना, मॉरीशस, सेशेल्स और तंजानिया जैसे देश शामिल है। जर्मनी और इजरायल जैसे 64 विकसित देशों ने भी 'रुपये' के जरिए कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई है। रूस और चार अफ्रीकी देश भी मंजूरी दे चुके हैं। 22 देशों में भारत ने वोस्ट्रो खाते खोले हैं। इनमें 12 भारतीय बैंकों को मंजूरी दी गई है। डॉलर, पाउंड और यूरो के उपरांत 'रुपया' आज चौथी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बन गया है। R B I द्वारा 'रुपये' का अंतरराष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद विदेशी कंपनियां भारत के साथ आसानी से व्यापार कर रही हैं, जिससे व्यापार और निवेश बढ़ रहा है, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, विदेशी ऋण भार को कम किया जा रहा है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा मिल रही है।

"भारतीय बैंकों, मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाने की जरूरत"
– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“हमारे घरेलू बैंको, मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसपर ध्यान देना जरूरी है”
-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
(7 जून 2022 को वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का उद्घाटन करने के बाद)

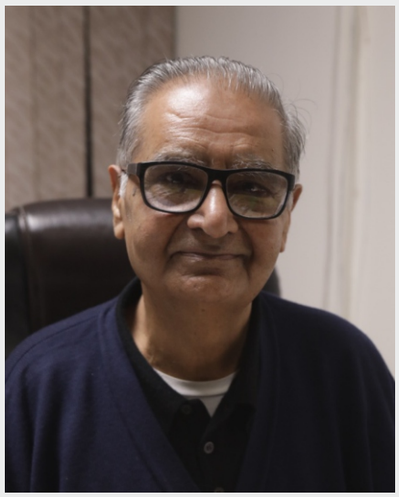

श्री बी.डी. नारंग

आर्थिक विशेषज्ञ

श्री बी.डी नारंग ‘रुपये’ के अंतरराष्ट्रीयकरण को मील का पत्थर बताते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वित्तीय संकटों के जोखिम को कम किया जा सकेगा। स्थिर और पूर्वानुमानित पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दिया जा सकेगा। भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को पूंजी नियंत्रण को उदार बनाना जारी रखना होगा। पर्याप्त पूंजी और तरलता भी आवश्यक होगा। विनियमों को और सरल बनाना होगा। दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी। अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाना होगा। इंस्पेक्टरराज खत्म करना होगा।

अंतरिक्ष अभियान

भारत का अंतरिक्ष अभियान,जो आज से 5 दशक पहले साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ था, वह अब चंद्रमा से होते हुए आदित्य L1 के माध्यम से निर्धारित कक्षा में पहुँच कर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। आदित्य L1 का हेलो ऑर्बिट सम्मिलन 6 जनवरी 2024 को पूरा हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस चंद्रयान की परिकल्पना की थी, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 23 अगस्त को साकार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो जाकर वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और उनको सैल्यूट किया। उन्होंने 23 अगस्त को प्रतिवर्ष 'नेशनल स्पेस डे' के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही जिस स्थान पर चंद्रयान-3 उतरा उसका नाम 'शिवशक्ति' और जहां चंद्रयान-2 की छाप पड़ी उसे 'तिरंगा' नाम दिया है। इसरो ने समुद्रयान मत्स्य 6000 को समुद्र के 6 कि.मी. अंदर तक भेजने के बाद ब्लैक होल का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है। मौजूदा सरकार ने अंतरिक्ष अभियान का बजट भी 130 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

"भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“भारत की अंतरिक्ष में ऊँची उड़ान”

“जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं,तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती हैं। ये पल अविश्वसनीय है। ये क्षण अद्भुत है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदीयमान भाग्य के आह्वान का है।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

डॉ. अखिलेश गुप्ता

सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डॉ. अखिलेश गुप्ता का कहना है कि चंद्रयान-3 की सफलता वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम और सरकार की अनुकूल नीतियों का परिणाम है। भारत आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिक मंगल और चंद्रमा के बाद अब आदित्य एल-1 के माध्यम से सूर्य की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। वेद-पुराणों में वर्णित बातें आज कल्पना लग सकती हैं, लेकिन कल की सच्चाई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 साल पहले एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना कल्पना लगता था, जो आज सच साबित हो चुका है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

यह आम आदमी की 'उड़ान' है

प्रधानमंत्री जी ने 27 अप्रैल 2017 को 'उड़े देश का आम नागरिक' यानि "उड़ान" योजना का शुभारम्भ किया। योजना का लक्ष्य न केवल क्षेत्रीय एयर कनेक्टीविटी को बढ़ावा देना है,बल्कि देश के आम आदमी को सम्मान के साथ हवाई जहाज में उड़ान भरना भी है। "उड़ान" के उद्देश्यों में हवाई यात्रा को सस्ता, सुलभ और व्यापक बनाना, आर्थिक विकास में सुधार लाना तथा क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना भी शामिल है। देश में आज नागरिक उड्डयन के लिए 149 से अधिक परिचालन हवाई अड्डे हैं, जिनमें 30 अंतरराष्ट्रीय, 12 सीमा शुल्क, 107 घरेलू और सैन्य हवाई अड्डों के भीतर कुछ और नागरिक उड्डयन एन्क्लेव शामिल हैं। 2030 तक 6, 2040 तक 15 और 2047 तक 30 से अधिक हवाई अड्डे बनाने की योजना पर काम चल रहा है।

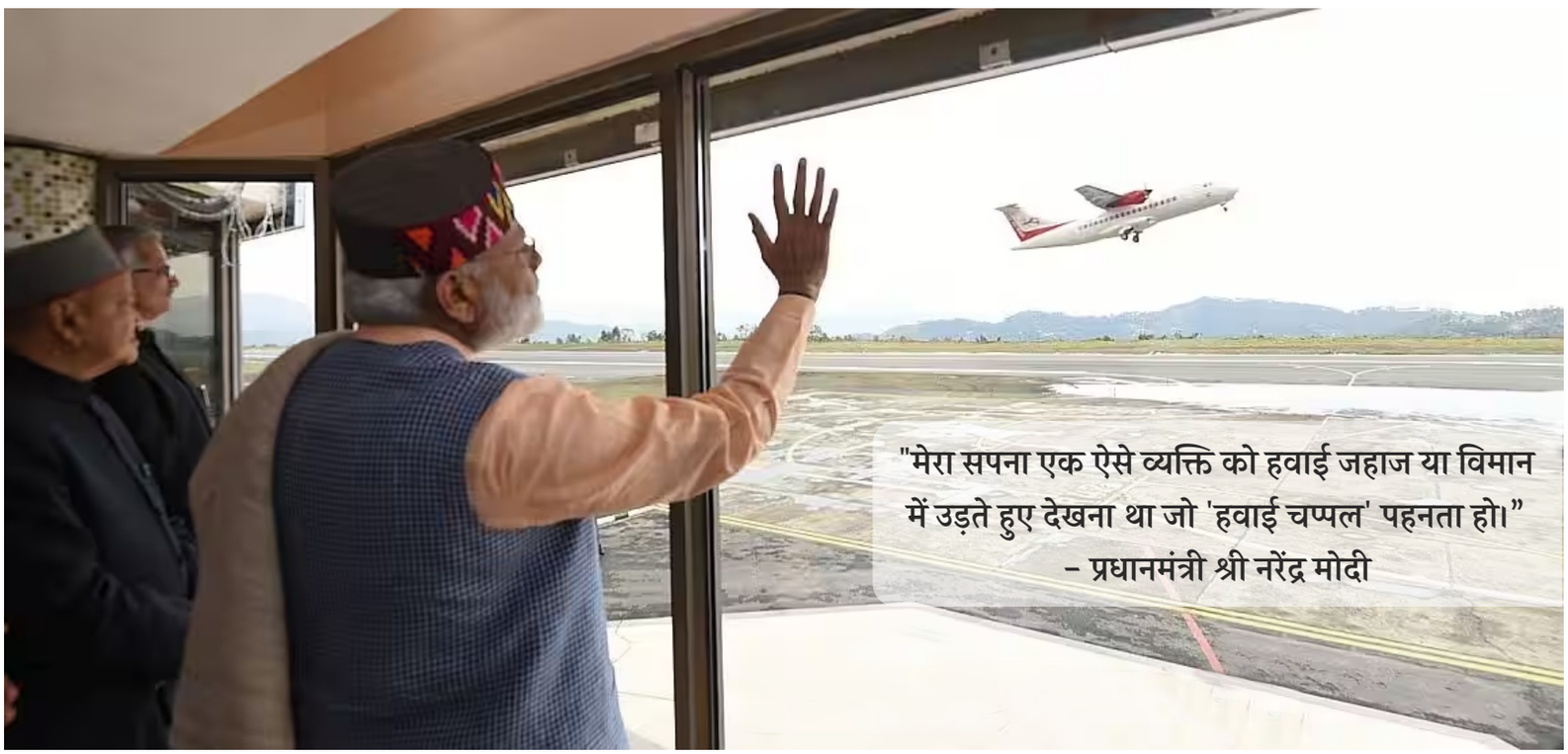

“मजाक ना उड़ाएं, सम्मान दें, आम आदमी को उड़ान दें”

श्री वी.पी. अग्रवाल

सेवानिवृत्त अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सेवानिवृत अध्यक्ष श्री वी.पी. अग्रवाल “उड़ान” योजना की सराहना करते हुए कहते हैं कि इसकी शुरुआत देश के आम आदमी को किफायती हवाई यात्रा मुहैया कराने और सभी छोटे-बड़े हवाई अड्डों को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया, परंतु योजना को और सफल बनाने के लिए अभी बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना होगा। संचालन का खर्चा कम करना होगा। फ्यूल पर सरचार्ज कम करना होगा। आप इंडियन एयरलाइन्स के नीजिकरण का भी समर्थन करते हैं।

नए भारत की ट्रेन

वंदेभारत

वंदे भारत ट्रेन को आधुनिक भारत की ट्रेन भी कहा जाता है। इस विश्वस्तरीय यात्री गाड़ी में ऑनबोर्ड इंफोटेमेंट, जीपीएस, सीसीटीवी, स्लाइडिंग डोर, फायर सेंसर एवं बॉयोटॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है। शताब्दी ट्रेनों की तुलना में इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम काफी कम है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 18 फरवरी 2019 को वाराणसी और दिल्ली के बीच चलाई गई थी। आज पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क विकसित हो रहा है। यह ट्रेन भारत की मेक-इन-इंडिया योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रेन का निर्माण भारतीय रेलवे की चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। एक वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आती है। इस ट्रेन की गति को अब 160 किमी प्रतिघंटा से बढ़ाकर 200 किमी प्रतिघंटा किया जा रहा है। आजादी के अमृतकाल में संपूर्ण भारत में 100 स्थानों पर वंदे भारत ट्रेन के संचालन की योजना है।

भारत में पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। इस ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेलवे द्वारा किया जाता था। इसके बाद ही मुंबई में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया जिसका नाम अब शिवाजी टर्मिनस रखा गया है। आज भारतीय रेलवे एक आधुनिक युग की तरफ बढ़ रही है।देश में आज प्रतिदिन 13523 ट्रेनें चलती है। रेलवे के पास 300 रेलवे यार्ड, 2300 माल ढुलाई केंद्र और 700 ट्रेन मरम्मत कारखाने हैं। भाप और डीजल के इंजन से निकल कर रेलवे आज अपने इंजनों को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में तब्दील कर रहा है। भारतीय रेलवे आज 16 जोन में ट्रेनों और मालगाड़ियों का संचालन करता है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में रेलवे का महत्वपूर्ण स्थान है। रेलवे के पास अपने लोकोमोटिव, कैरिज वैगन, पुल कारखाने एवं सिग्नल कारखाने हैं। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीकरण किया गया था। जबकि आजादी से पूर्व मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1986 में रेलवे ने स्वयं का कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम विकसित किया था।

"देश में बुनियादी ढ़ांचे के विकास की यह गति और पैमाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिलकुल मेल खाता है। आत्मविश्वास से भरा भारत अपने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है।"

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

श्री आलोक कंसल

सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, भारतीय रेल

पूर्व महाप्रबंधक श्री आलोक कंसल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का विस्तार तेजी से हो रहा है। एक ओर जहां वंदे भारत और तेजस जैसी सुपरफास्ट रेल गाड़ियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे ट्रैक का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के कार्य ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आपके अनुसार अब वह दिन भी दूर नहीं जब आम आदमी विंडो पर जाएगा और उसे टिकट मिल जाएगा, क्योंकि यह सरकार का लक्ष्य है। आप सरकार को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव भी देते हैं।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

कारीगर को कारोबारी बनाने की योजना

भारत सरकार ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 18 प्रकार के दस्तकारों को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 13000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। दस्तकारों को आधुनिक कौशल विकास का प्रशिक्षण एवं उन्नत टूलकिट प्रदान कर रोजगार बढ़ाने के लिए ऋण की व्यवस्था सरकार ने की है। इस योजना से भारत की परंपरागत दस्तकारी दुनियाभर में पहुंचेगी जिसका सीधा लाभ करोड़ो दस्तकारों को प्राप्त होगा। मेक-इन-इंडिया के सपने को भारत के दस्तकार विश्वस्तर पर लेकर जाएंगे। अपने पैतृक व्यवसाय को चलाने वाले हुनरमंद दस्तकार पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोकल-फॉर-वोकल की अर्थव्यवस्था को नई ऊचाईयों पर लेकर जाएंगे।

"हमारे विश्वकर्मा साथी मेक-इन-इंडिया की शान हैं। विश्वकर्मा साथियों को अब बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा।सरकार ने यह सुनिश्चित किया हैं कि इस ऋण का ब्याज बहुत कम रहे।"

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

श्री राम चंद्र जांगड़ा

सांसद, राज्यसभा

देश के सभी पेशेवर लोगों को भारत सरकार ने इस योजना के साथ जोड़ा है। दर्जी, स्वर्णकार, बढ़ई, खिलौने बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, कुम्हार, लुहार, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, मोची, धोबी और नाई बंधुओं के लिए यह योजना जीवन बदलने वाली साबित होगी। प्राचीन काल में भारत की अर्थव्यवस्था का आधार इन्हीं दस्तकारों पर निर्भर थी। आजादी के बाद दस्तकार बंधुओं के उत्थान के लिए यह ऐसी पहली योजना है जो देशभर के दस्तकार भाईयों को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह विजन हैं कि देश के हर हुनरमंद,दस्तकार एवं शिल्पकार बंधु को इस योजना का लाभ मिले।

पर्यटन नीति

“प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पर्यटन को लगे पंख”

प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश में पर्यटन को पंख लग गए हैं। देश में पर्यटन की नई तस्वीर उभर रही है। यह तस्वीर उन चुनिंदा 50 पर्यटन स्थलों की है,जिसमें समुद्रीय तटीय, वन्यजीव, रोमांचकारी, सांस्कृतिक, हिमालयन और आध्यात्मिक पर्यटन शामिल है। वेडिंग डेस्टिनेशन,खेलों और अन्य आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जहां सीमावर्ती गांवों में पर्यटन की मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है,वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित राज्यों और अलग-अलग मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस वित्त वर्ष में 2400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

“पर्यटन है देश में बदलाव का रास्ता”

"जब हम पर्यटन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक फैंसी शब्द है और यह केवल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है,जो संपन्न हैं। भारत के संदर्भ में, पर्यटन का दायरा बहुत बड़ा है और यह सदियों से हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

अतिथि देवो भव:

श्री के.बी. काचरू

मानद अध्यक्ष और प्रधान सलाहकार,
दक्षिण एशिया रेडिसन होटल समूह

श्री काचरू कहते हैं कि यह सरकार की नीतियों का ही प्रतिफल है कोविड के बाद पर्यटन क्षेत्र को फिर से पंख लगे हैं। वास्तव में पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ है। इसलिए मोदी जी ने विदेशों में बसे भारतीयों से आह्वान किया कि वे कम से कम तीन परिवारों को भारत लाकर अपना देश दिखाएं। ‘देखो अपना देश’ योजना का भी शुभारम्भ हुआ है। आज ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करके तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपका सुझाव है कि सरकार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर निवेश को बढ़ावा दे।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

लक्षद्वीप

की बढ़ती लोकप्रियता

भारत के संपन्न पर्यटन क्षेत्र के लिए कर रहा उत्प्रेरक का काम

"मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहां के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूं। जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप को आपकी सूची में होना चाहिए"
– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (3 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप की यात्रा पर)

प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप की यात्रा कर यह सिद्ध कर दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। लक्षद्वीप के शांत तटों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस सुरम्य द्वीपसमूह की सुंदरता और आकर्षण को तो उजागर किया ही है, इसके प्राचीन समुद्र तटों, जीवंत मूंगा चट्टानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर वैश्विक ध्यान भी आकर्षित किया है। अरब सागर में 36 द्वीप को समेटता यह केंद्र शासित प्रदेश दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है, जो प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों को खूब आकर्षित करता है। भारत के संपन्न पर्यटन श्रेत्र के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री जी ने 1156 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया,जिनमें कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, कदमत के लिए एक "कम तापमान" थर्मल अलवणीकरण संयंत्र, एक पेयजल वितरण परियोजना, एक बैटरी-समर्थित सौर ऊर्जा, कावारत्ती में इंडिया रिजर्व बटालियन परिसर में एक नए प्रशासनिक ब्लॉक और 80 पुरुष बैरक शामिल है।

श्री एस.पी. अग्रवाल

पूर्व प्रशासक, लक्षद्वीप

श्री अग्रवाल जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और कहा कि मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और आतिथ्य सेवाओं में पर्याप्त निवेश को प्रेरित करेगी, जिससे द्वीपसमूह वैश्विक पर्यटकों के लिए एक सुलभ और प्रतिष्ठित गंतव्य बन जाएगा। आपने पर्यटन में संभावित उछाल के बीच, पारिस्थितिक सावधानी बरतने का सुझाव भी दिया। आपके अनुसार यदि लक्षद्वीप पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए जाने चाहिए कि द्वीप प्लास्टिक से मुक्त रहें। श्रृंखला के कई द्वीप पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

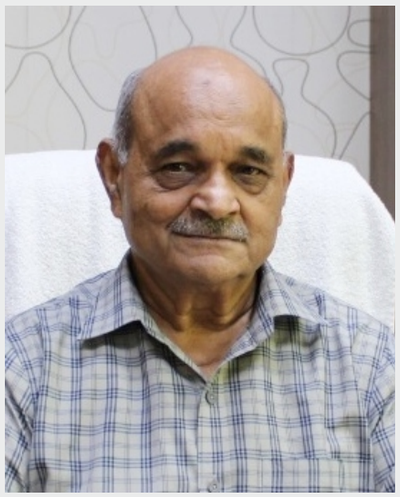

“विकास का प्रतिमान सुमंगलम”

डॉ. बजरंग लाल गुप्ता

अर्थशास्त्री एवं पूर्व संघ चालक, उत्तर क्षेत्र

डॉ. बजरंग लाल गुप्ता एक अर्थशास्त्री हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। देश के आर्थिक विकास को लेकर आपका शोध और चिंतन अत्यंत उपयोगी है। आपके अनुसार पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित जीडीपी की गणना दोषपूर्ण है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी की गई है,जो भारतीय परिपेक्ष में अनुचित है। आप ने 'विकास का नया प्रतिमान सुमंगलम' नामक पुस्तक में विकास की अवधारणा को विस्तार से परिभाषित किया है,जिसके अनुसार समस्त देशवासियों के सामाजिक सुख में समग्र वृद्धि करना ही एकमात्र लक्ष्य है।

5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

भारत इस समय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री और उनके मत्रिमंडलीय सहयोगियों के अथक प्रयास से देश की अर्थव्यवस्था आज तेजी से आगे बढ़ रही है। वह दिन दूर नहीं,जब अर्थव्यवस्था के मामले में भारत तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा।

आगे बढ़ने के लिए विकास को गति देना जरूरी। विकास को लेकर लोगों की सोच बदली है। अब बिजली के खंभे नहीं, 24 घंटे बिजली की मांग है। अब मोबाइल नहीं हाई स्पीड डाटा की मांग है। देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनामी बनाने का लक्ष्य है। 2014 में GDP 112.33 लाख करोड़ था जो अब 272.4 लाख करोड़ से अधिक है। 5 साल में हमने इकोनामी को 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ाया।

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मोदी की गारंटी

श्री विनीत लोहिया

चेयरमैन, लोहिया ग्लोबल

श्री विनीत लोहिया जी देश के बड़े उद्योगपति और निर्यातक हैं। आप हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी आप एक स्थापित नाम हैं। श्री लोहिया के अनुसार सरकार ने अर्थव्यवस्था की नींव रखने का कार्य पूरा कर लिया है। अब इमारत तेजी से बनेगी। लेकिन इसके लिए देश के हर नागरिक को विदेशी सामान का मोह त्यागकर स्वदेशी उत्पाद अपनाने होंगे। सरकार को भी नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगानी होगी।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

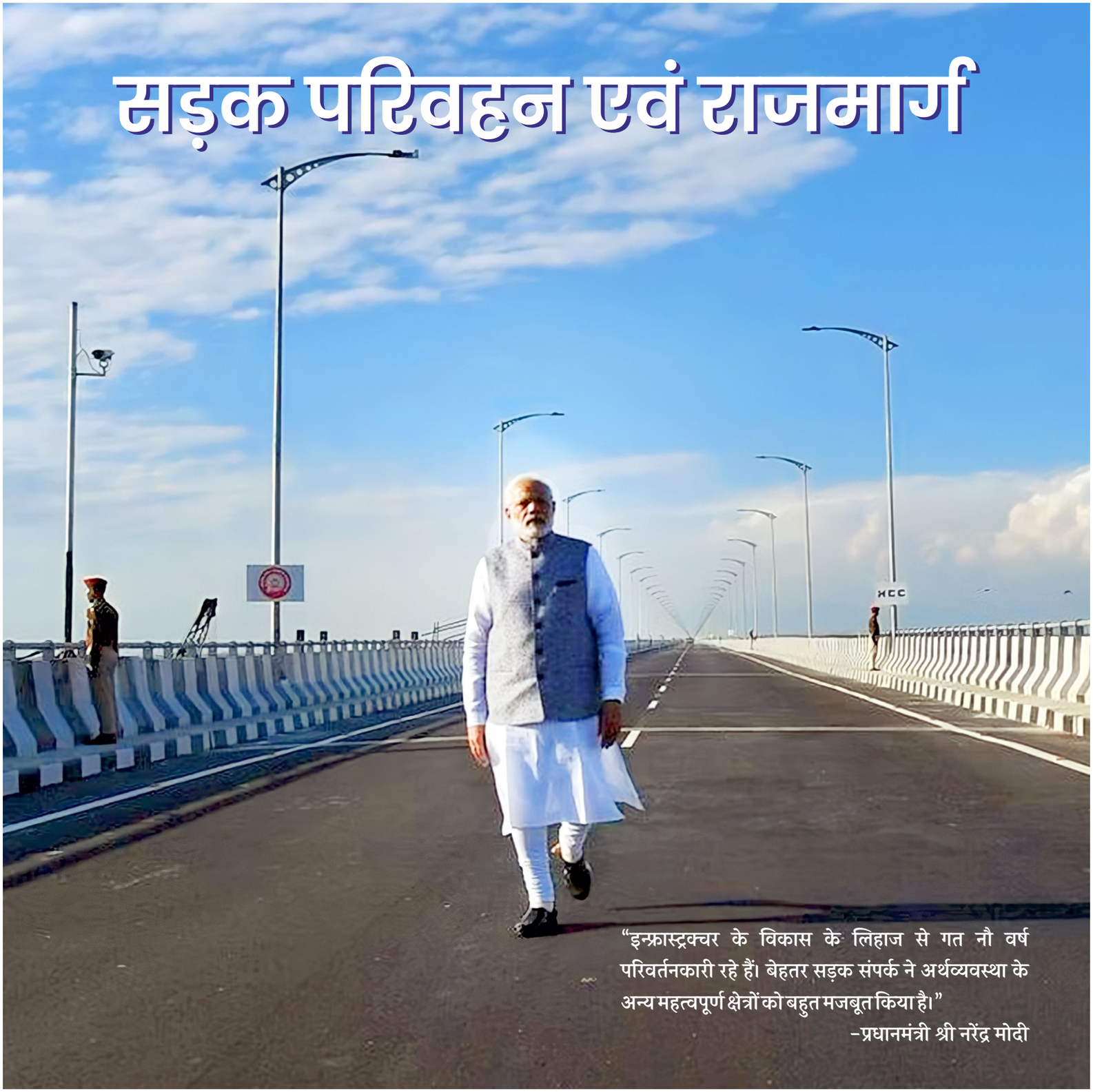

"इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिहाज से गत नौ वर्ष परिवर्तनकारी रहे हैं। बेहतर सड़क संपर्क ने अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बहुत मजबूत किया है।"

–प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“सड़क बनाओ, विकास का पहिया तेजी से घुमाओ”

श्री अजय सिंघल

चेयरमैन, ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

श्री अजय सिंघल कहते हैं कि इससे खर्चे में दो से तीन प्रतिशत की कमी आई है। जीएसटी और अच्छी सड़कों के कारण ट्रांस्पोर्टरों का लाभ बढ़ा है, क्योंकि पहले जहां ट्रक के दो चक्कर लगते थे, वहां अब चार चक्कर लगा रहे हैं। जीएसटी के कारण भी कागजी कार्रवाई में कम समय लग रहा है। सड़कों के सुधार के कारण अब दुर्घटनाएं कम होती हैं। आप सरकार को इंस्पेक्टर राज समाप्त करने, टोल टैक्स कम करने, परिवहन केंद्रों का बेहतर रखरखाव करने, ड्राइवरों के खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था करने के साथ रोड नेटवर्क को और बढ़ाने तथा सड़कों पर पड़ने वाले गढ़ों को बिना देर किए ठीक करने का सुझाव भी देते हैं।

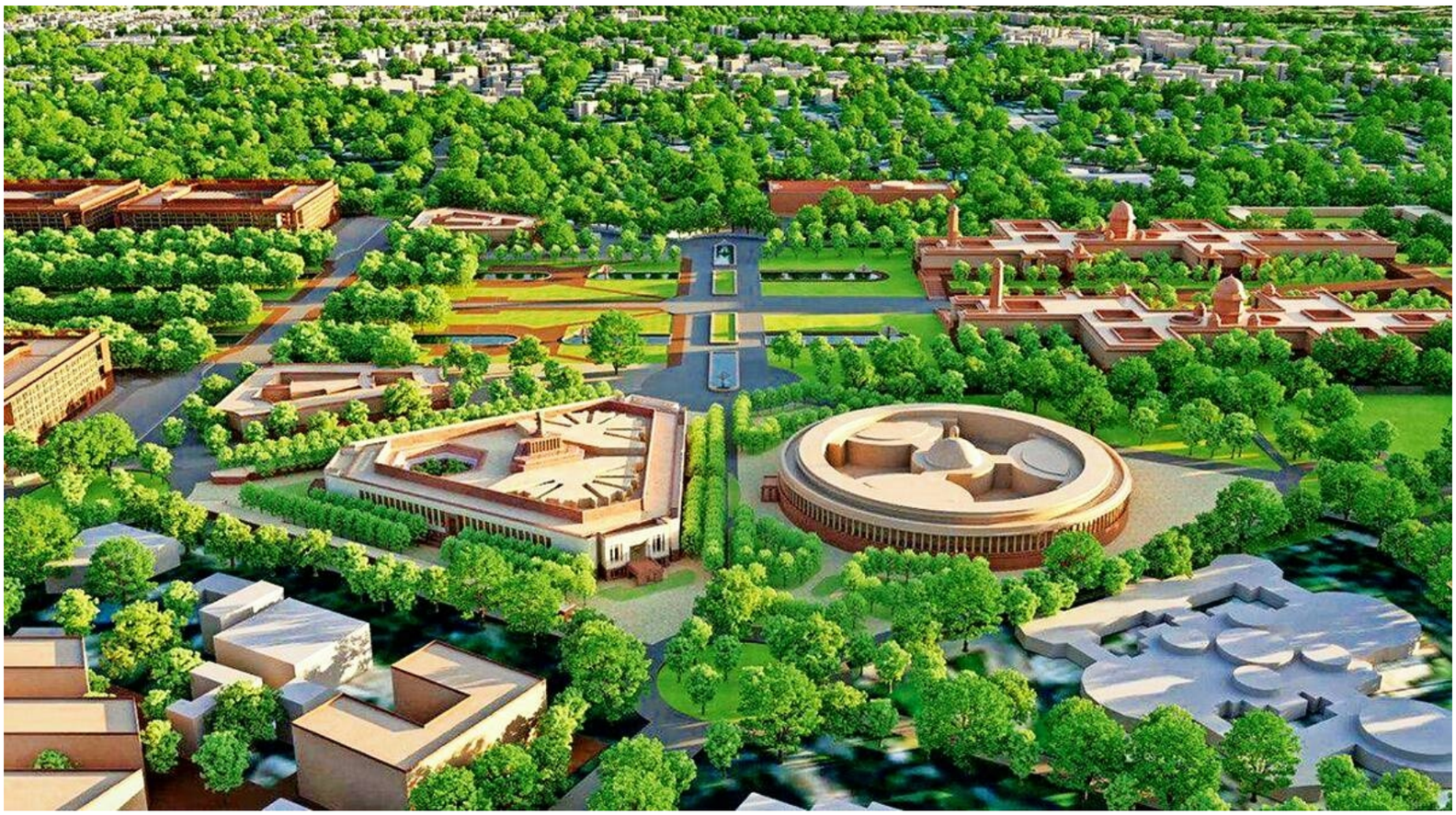

सेंट्रल विस्टा

प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया। उन्होंने इसकी आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी थी। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है, जिस पर अब तक 970 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पूरी परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के करीब 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को पुनर्विकसित किया जा रहा है।

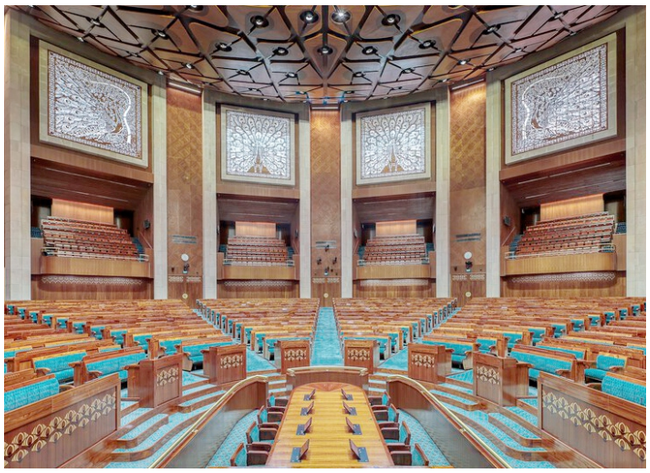

'इंडिया' नहीं 'भारत'

"यह सिर्फ भवन नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं।" – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मोदी है तो मुमकिन है

श्री नरेश बंसल

सांसद, राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, बीजेपी

उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री बंसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने नई संसद के उद्घाटन के समय भवन का भ्रमण किया और "नमो इम्पैक्ट" को बताया कि नया संसद भवन भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रतीक है। इसके निर्माण से पूरे विश्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। "एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्धशाली भारत" का प्रतीक है यह भवन। श्री बंसल जी को संसद में इंडिया नहीं भारत का मुद्दा उठाकर उसे निर्णायक स्थिति तक ले जाने का श्रेय जाता है।

भारत: लोकतंत्र की जननी

विश्व का सबसे पुराना
सबसे बड़ा लोकतंत्र

भारत में आध्यात्मिक लोकतंत्र का इतिहास हजारों-हजार साल पुराना है। इसके अनेकानेक उदाहरण रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी वर्णित है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनायी थी उसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सोंप दी है, उस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक देश एक चुनाव अभियान को मूर्त रूप दिया जाएगा।

"वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ़ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं। इससे विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में "वन नेशन, वन इलेक्शन" पर गहन मंथन आवश्यक है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी संयुक्त राष्ट्र सहित देश में कई अहम पदों पर रहे हैं। आपको कंबोडिया और नामीबिया सहित देश के कई राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का अनुभव है। आपके अनुसार "एक देश,एक चुनाव" की व्यवस्था आदर्श है। यह विकासोन्मुखी है। इससे न केवल देश के 30 हजार करोड़ रुपए तक बचेंगे, बल्कि आचार संहिता के कारण बाधित होने वाले विकास कार्य भी नहीं रुकेंगे। आप चुनाव प्रक्रिया सरल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपनाने के साथ ही मतदाता सूचियों को आधार से लिंक कराने का सुझाव भी देते हैं।

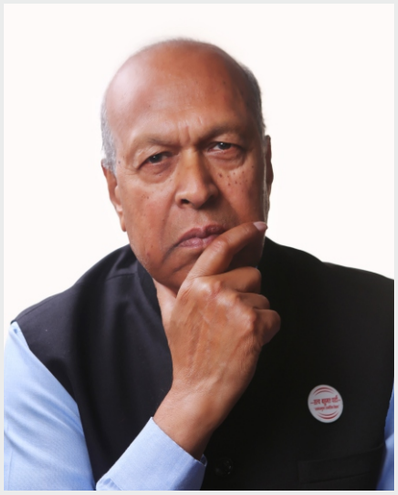

श्री सत्यदेव चौधरी

समाजसेवी और उद्योगपति

श्री सत्यदेव चौधरी एक चिंतक, समाजसेवी और उद्योगपति हैं। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के निमित्त आपने एक राजनीतिक दल "सत्य बहुमत पार्टी" का गठन किया है। आप मानते हैं कि "एक देश एक चुनाव" का विचार अच्छा है। लेकिन यह भी देखना होगा कि आजादी के समय ही शुरू की गई यह व्यवस्था पटरी से क्यों उतरी? आपका दृढ़ विश्वास है कि राजनीति को गठबंधनमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त बनाकर ही सुधारा जा सकता है। इसके लिए वोटों के बहुमत वाली व्यवस्था अपनानी होगी।

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

"विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के करीब चार लाख लोगों की जान बच रही है यह निचले तबके के लोग हैं।" – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

नमामि गंगे

भारतीय जनमानस के लिए गंगा, गंगा नहीं है, गंगा मैया है। माँ गंगा की पूजा-अर्चना सनातन काल से होती आ रही है। गंगा जमीन पर ही नहीं, अपितु मनुष्यों के मनोलोक और अवचेतन में भी बहती हैं। ऋषि-मुनि ही नहीं, आम आदमी भी माँ गंगा के बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता। गंगा तो जन-जन में रची-बसी हैं। गंगा के बिना मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

“गंगा गंगा नहीं है गंगा मैया है”

स्वामी चिदानंद जी सरस्वती

अध्यक्ष, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

स्वामी चिदानंद सरस्वती जी प्रतिष्ठित संत हैं। आपने अपना पूरा जीवन माँ गंगा की सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित किया हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने “नमामि गंगे” और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण की अद्भुत आधारशिला तैयार की है। इसलिए अब सरकारी योजनाएं असरकारक सिद्ध होने लगी हैं। सरकार के तालमेल से व्यापक स्तर पर कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि लोग जागरूक हों और इस अभियान में सरकार का सहयोग करें,क्योंकि जल है, तो जीवन है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

पराक्रम दिवस

(अंडमान निकोबार द्वीप समूह)

देश के महापुरुषों का सम्मान सौभाग्य की बात होती है। महापुरुषों का सम्मान करना भारतीय सनातन संस्कृति भी है। पुरातन संस्कृति के तहत ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ भारती के दो सपूतों नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर को सम्मान ज़ापित किया है। इन सेनानियों की स्मृति में केंद्र सरकार ने रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया। वस्तुतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखण्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 30 दिसंबर 1945 को अंडमान-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जबकि वीर सावरकर ने अंडमान की सेल्यूलर जेल में अनेक वर्षों तक यातनाएं सहीं।

महापुरुषों ने बनाया आज का हिन्दुस्तान प्रधानमंत्री ने दिया पूरा सम्मान

सेल्यूलर जेल

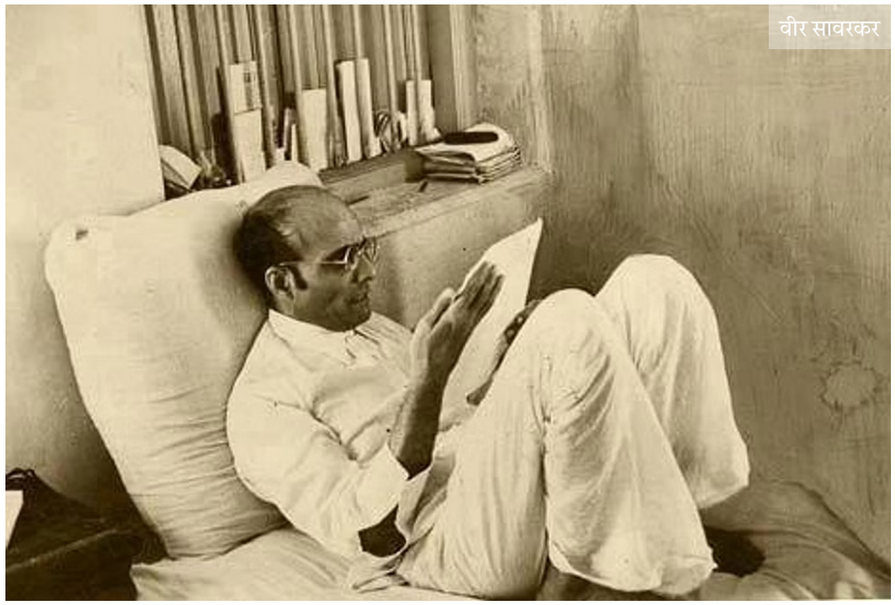

वीर सावरकर

प्रो. जगदीश मुखी

पूर्व राज्यपाल, असम एवं नागालैंड

असम एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी रहे हैं। आपका कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी को वह सम्मान दिलाने का कार्य किया है,जिसके वह हकदार थे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी दूरदृष्टि और इच्छाशक्ति से अंडमान-निकोबार सहित पूर्वोत्तर को भी एक नई पहचान दी है। अंडमान-निकोबार समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आज विकास की गंगा बह रही है।

3 तलाक

उत्पीड़न से मिली मुक्ति
बराबरी का मिला हक

देशभर की मुस्लिम महिलाएं आज प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता वयक्त कर रही हैं। उनके दीर्घायु की कामना कर रही हैं। केंद्र सरकार की प्रशंसा कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इन्हें 1400 साल पुरानी तीन तलाक जैसी कूप्रथा से मुक्ति दिलवाई है। ये महिलाएं आज जो खुशहाल जीवन जी रही हैं, जिनके जीवन में सुख-शांति आई है, उन्हें तीन तलाक ने तबाह-बर्बाद कर दिया था। पीड़िताएं जब मायके पहुंचतीं, तो वहां भी ताने ही मिलते। ऐसे में इन्हें अपने से ज्यादा बच्चों की चिंता सताती। लेकिन कानून बना, तो महिलाओं को न सिर्फ संबल मिला, बल्कि उत्पीड़न से मुक्ति और बराबरी का हक भी मिला।

"तीन तलाक के पक्ष में जो भी बात करते हैं, जो भी इसकी वकालत करते हैं, वो वोट बैंक के भूखे लोग, मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से केवल बेटियों पर अन्याय नहीं होता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है।"

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

एक देश-एक कानून

समान नागरिक संहिता एनडीए सरकार के प्रमुख वादों में से एक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) एक देश-एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत देश के सभी धर्म, पंथ और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है।

"यूनिफार्म सिविल कोड के नाम पर भी अब लोगों को भड़काया जा रहा है। दो कानून से घर नहीं चल पाएगा,जबकि भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

डॉ. नंद किशोर गर्ग

कुलाधिपति, महाराजा अग्रसेन विश्विद्यालय

डॉ. नंदकिशोर गर्ग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, शिक्षाविद, और विचारक हैं। आप त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक चुने गए। आपका कहना है कि समान नागरिकता कानून से किसी के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। गोवा में और दुनियाभर के कई मुस्लिम देशों में भी यह पहले से लागू है। IPC (आईपीसी) में पहले ही सबके लिए समान कानून लागू है। तरक्की पसंद हर व्यक्ति यूसीसी के हक में है।

डिजिटल भारत

"डिजिटल भारत" भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। डिजी लॉकर इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे प्रपत्रों को संभालकर रखना हमेशा से लोगों के लिए बड़ी चुनौती रही है। कई बार बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं में जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज़ सीधे डिजीलॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन, वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो गया है।

“पावर टू एम्पावर”

“सशक्त बनाने की शक्ति”

डॉ.पवन दुग्गल

साइबर एक्सपर्ट

डॉ.पवन दुग्गल का कहना है कि कैशलेस इकोनॉमी समय की जरूरत है। मोदी सरकार ने देश को कैशलेस लेनदेन की तरफ ले जाने के लिए और काले धन पर रोक लगाने के लिए जिस तरह से नोटबंदी की, वो प्रशंसनीय है। लेकिन डिजिटल और कैशलेस लेनदेन में साइबर अपराधों का खतरा हर समय बना रहता है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इससे जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जी की पहल पर 28 अगस्त 2014 को देशभर में प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभारम्भ किया गया। उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाना और उसे आर्थिक रूप से सबल बनाना है। लाभार्थी जन-घन खातों में अपनी बचत जमा कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, अपने खाते में पैसे मंगवा सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, बीमा और पेंशन की सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें 176,912.36 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस योजना की उपलब्धियों की प्रशंसा की है।

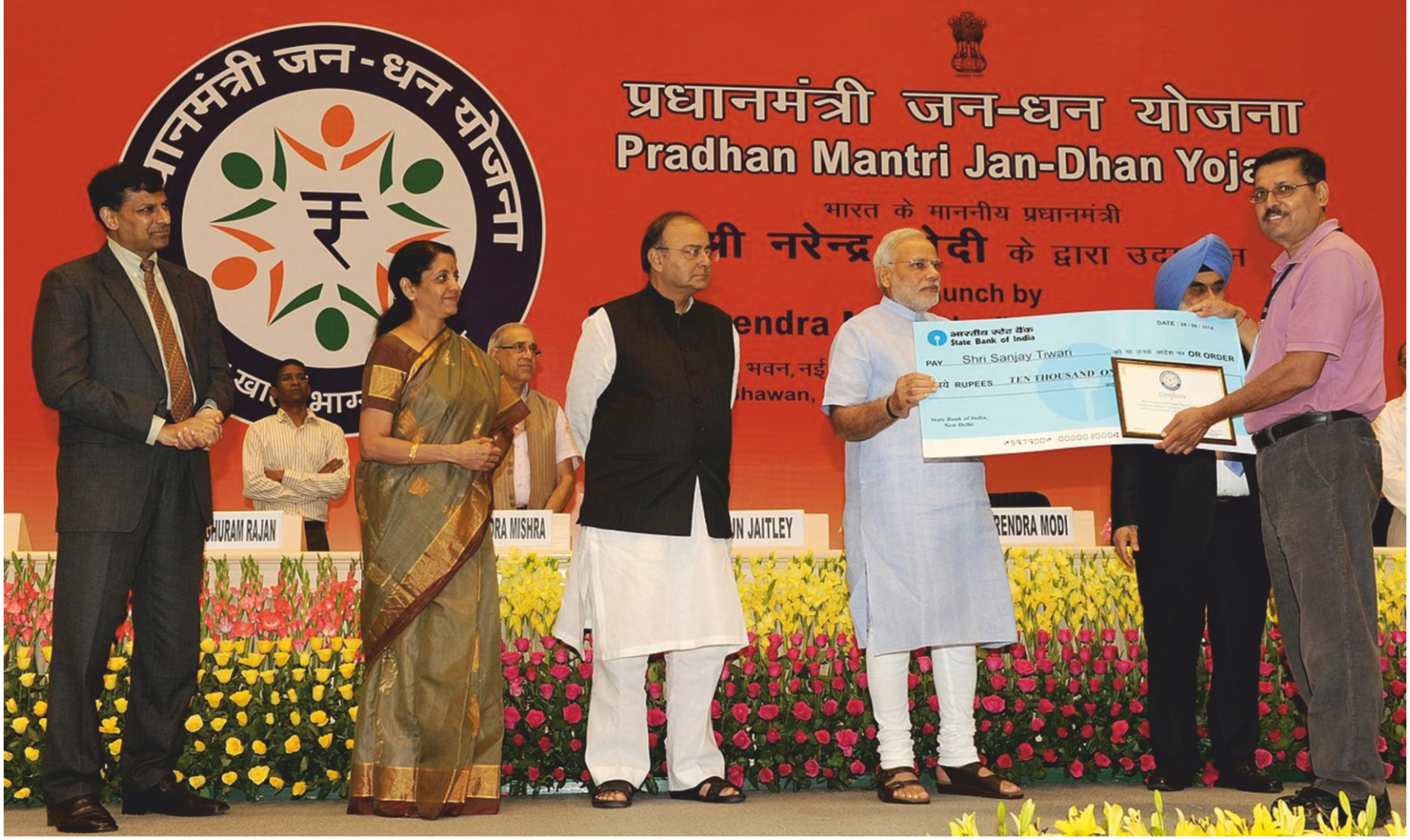

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

"आज भारत के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली एक पहल पीएम जन-धन ने वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ अनगिनत भारतीयों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। जन-धन योजना से पारदर्शिता बढ़ाने में भी सहायता मिली है। मैं उन सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं,जिन्होंने पीएम जन-धन को सफल बनाने के लिए काम किया है। उनके प्रयासों ने भारतीयों के जीवन को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाना सुनिश्चित किया है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

"सुखस्य मूलं धर्म, धर्मस्य मूलं अर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यं"

डॉ. तेजेन्द्र मोहन भसीन

पूर्व चैयरमैन, इंडियन बैंक

डॉ. भसीन का कहना है कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ की गई है। सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के उन खातों में पहुंच रही है। मौजूदा सरकार ने 15 सरकारी बैंकों का विलय किया, सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई, जिससे डूबत ऋण में उल्लेखनीय कमी आई है।

स्वावलंबन से सशक्तिकरण

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति की जागृति एवं सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है। सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण अभियान एक समन्वित महिला स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण आंदोलन है, जो निराश्रित एवं निर्धन महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ज्योति प्रदान करने हेतु कृतसंकल्प है। अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा संबल प्रदान किया जाता है। अब तक लाखों महिलाओं को व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

पूर्व सांसद, बाराबंकी

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत 16वीं लोकसभा में चौथी सबसे कम उम्र की सांसद थीं। फिलहाल आप उत्तर प्रदेश बीजेपी की महामंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आपने एक लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रियंका जी का स्पष्ट कहना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास असंभव है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

नारी शक्ति की जागृति एवं सशक्तिकरण

"हमारी नारी शक्ति की उपलब्धियों के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। हम भारत की प्रगति में महिलाओं की भूमिका की बहुत सराहना करते हैं। सरकार महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहेगी।"
– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पद्मश्री श्रीमती संतोष यादव

पर्वतारोही

पद्मश्री संतोष यादव एवरेस्ट पर्वत पर दो बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। आप पहली ऐसी महिला हैं,जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में विजयदशमी पर्व के अवसर पर आयोजित वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। आपका कहना है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है। लेकिन महिला सशक्तिकरण समाज के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आप महिलाओं,बच्चियों और खिलाड़ियों से आह्वान करती है कि वे अपनी योग्यता को बढ़ाएं, जिज़ासु बनें, भय मुक्त रहें और भारतीय संस्कृति को अपनाकर शांति से कार्य करती रहें।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

महिला आरक्षण

"संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सर्वसम्मति से पारित होना महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।"
– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नरेन्द्र मोदी सरकार ने 20 सितंबर को लंबी बहस के बाद लोकसभा में बहुमत के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करा लिया। 21 सितंबर को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया। राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद संसदीय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला महिला आरक्षण विधेयक अब कानून बन गया। अब देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं। फिलहाल महिलाओं को सांसद और विधायक बनने के लिए 15 साल तक ही आरक्षण मिलेगा। 15 साल बाद महिला आरक्षण को बरकरार रखने के लिए संसद से दोबारा इस कानून को स्वीकृत करना होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं होगा क्योंकि इस विधेयक के प्रारुप एवं प्रक्रिया हेतु जनगणना होना जरूरी है। जनगणना के नए आंकड़े सामने आने के बाद महिलाओं के लिए विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों का निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा।

श्रीमती शालीना चतुर्वेदी

कथक नृत्यांगना एवं मंत्र थेरपीस्ट

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, नारी सशक्तिकरण, पौराणिक संस्कारों और सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक पहलुओं को इस तरह से समाहित किया है कि उसका असर देश में दिखाई दे रहा है। देश को एक अच्छा नेतृत्व नरेन्द्र मोदी जी दे रहे है। हम सभी को मिलकर उनका साथ देना होगा। नरेन्द्र मोदी जी का हर कार्य प्रेरणादायक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व है। इससे देश की महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। देश की संस्कृति को ऊंचे शिखर पर ले जाने वाले नरेन्द्र मोदी महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े प्रहरी है।

एक्ट-ईस्ट नीति

ढोला सदिया पुल

पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और विकास की गति प्रदान करने के प्रयोजन से पूर्ववर्ती सरकार की लुक ईस्ट नीति को बदला गया। नरेंद्र मोदी सरकार के नौ वर्षों में विकास पर यहां 3.37 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क को 8,480 किलोमीटर से 16,000 किमी तक विस्तारित किया गया है। हवाईअड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। रेल कनेक्टिविटी में भी लगातार सुधार हो रहा है। नीति का उद्देश्य भी द्वीपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल देना है। भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।

"मेरे मंत्री 400 बार गए हैं, मैं खुद 50 बार गया हूं। ये आंकड़ा नहीं है, ये साधना है। नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। मैं पिछले 9 साल के प्रयासों से कहता हूं, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। नॉर्थ ईस्ट के समस्याओं की जननी कांग्रेस है। कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग की बलि चढ़ गया। हर व्यवस्था उग्रवादी संगठन की मर्जी से चलती थी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आपने (कांग्रेस) कभी पूर्वोत्तर की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

(10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए)

“सर्वदा शुभ पूर्वोत्तर”

प्रोफेसर कपिल कुमार

शिक्षाविद एवं पूर्वोत्तर विशेषज्ञ

पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञ प्रोफेसर कपिल कुमार जी कहते हैं कि पहले केवल ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ थी, उस पर कार्य नहीं हुआ। परंतु अब केंद्र की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति के हिसाब से वहां का विकास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में पर्यटन और व्यापार की असीम संभावनाओं को देखते हुए पिछले 9 साल में काफी कार्य हुए हैं। काफी कार्य किया जाना बाकी भी है, क्योंकि 65-67 साल से रुके हुए कार्यों को 10 साल में पूरा कर पाना संभव नहीं है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

“पूर्वी एशियाई देशों का प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर”

श्री जयंत मल्ला बरुआ

पर्यटन मंत्री, असम

असम के पर्यटन मंत्री श्री जयंत मल्ला बरुआ बताते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कठोर कदम उठाए हैं,जिससे यहां आने वाले पर्यटकों के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ है। डबल इंजन की सरकार होने से असम में विकास की रफ्तार वास्तव में दोगुनी हुई है। राज्य सरकार ने असम में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स और स्टेकहोल्डर्स को विभिन्न सुविधाएं और इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे हैं।

निर्मल, संतुलित और सुखद मेघालय

श्री एलेग्जेंडर लालू हेक

पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री, मेघालय

मेघालय सरकार में मंत्री श्री एलेग्जेंडर लालू हेक का कहना है कि केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर में तीव्र गति से विकास हुआ है। सड़कों की हालत में अकल्पनीय सुधार हुआ है। शांति स्थापित हुई है। आज मेघालय पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में से एक है। पूर्ववर्ती सरकारों ने लोगों के मन में भय उत्पन्न करने का कार्य किया, कि पूर्वोत्तर में अशांति है। मीडिया ने भी छिटपुट घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, जिससे यहां के विकास को काफी नुकसान पहुंचा है। वास्तव में मेघालयवासियों के खून में ही आतिथ्य सत्कार समाहित है।

आत्मनिर्भर भारत

प्रधानमंत्री जी के महा-अभियान 'आत्मनिर्भर भारत' का उद्देश्य देश और देशवासियों को स्वावलंबी बनाना है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करना है। अभियान को अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया। वर्ष 2020 में अभियान का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की। इसका लक्ष्य वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुरक्षा अनुपालन में सुधार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयात पर निर्भरता को कम करना है।

"आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरे करने का भरोसा पैदा हुआ है। भारत में गरीबी तेजी से कम हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने एक वर्किंग पेपर में लिखा कि भारत ने अति गरीबी को लगभग खत्म कर दिया है। उसने भारत की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कहा है कि यह लॉजिस्टिकल मार्वल है। पिछले 5 साल में भारत में साढ़े तेरह करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।"

-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“वोकल फॉर लोकल
लोकल टू ग्लोबल”

श्री कश्मीरी लाल

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, स्वदेशी जागरण मंच

श्री कश्मीरी लाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आपके अनुसार 22 नवंबर 1991 को जिस उद्देश्य के साथ स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत वाली सोच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे देशवासियों के मन में भी अच्छा भाव जागृत हुआ है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऐमज़ॉन, वॉलमार्ट और अलीबाबा जैसी कंपनियों को देश में खुदरा कारोबार की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए न केवल कड़े कानून बनाए जाएं,बल्कि उनका क्रियान्वयन भी कड़ाई से किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

शिक्षा मंत्रालय

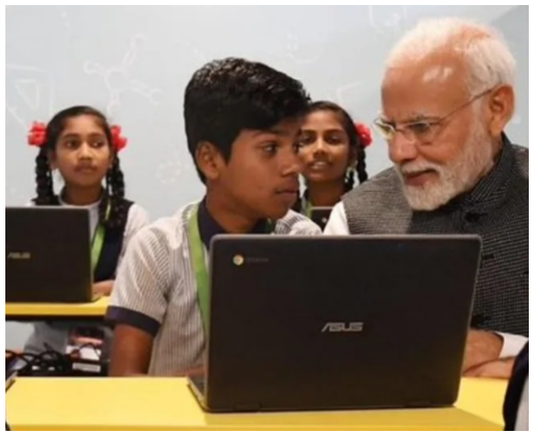

आईआईएम, मुंबई

मानव जीवन में अत्याधुनिक शिक्षा का गहन महत्व हैं। शिक्षा की इसी महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री की पहल पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई। शिक्षा नीति में बदलाव कुल 34 साल के अंतराल के बाद किया गया है। यह बदलाव जरूरी था, क्योंकि इसे शिक्षार्थी और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। नीति 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियत है।

प्रो. मनोज कुमार तिवारी

निदेशक, आईआईएम, मुंबई

आईआईएम, मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी जी का कहना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार लाना और कार्यप्रणालियों को सुव्यवस्थित करना है। सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र के लिए एक वरदान है, क्योंकि सरकार ने शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण सामने रखा है, जो प्रासंगिक और अत्याधुनिक है। सरकार चाहती है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली अन्य देशों से बेहतर हो। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (नीटी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में शामिल किया और उसे देश का 21वां आईआईएम बनाया।

"शिक्षार्थियों का यह नारा है
शिक्षा का अधिकार हमारा है"

"नई शिक्षा नीति मंथन के साथ बनी है। कोटि-कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है। भारत की धरती से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी है। इसमें हमने कौशल्य पर बल दिया है, यह ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नई आशा लेकर आई है। भारत की शिक्षा नीति से जुड़ी हुई हमारी शिक्षा नीति भाषा के बंधनों को तोड़ गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ताकत देगी।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पद्मश्री डॉ. महेश वर्मा

कुलपति, जीजीएस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली

डॉ. महेश वर्मा जाने-माने दंत चिकित्सक हैं। सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं। आजकल आप दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आपका कहना है कि बदलाव का हमेशा स्वागत होना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में सबके साथ चलना समय की आवश्यकता है। नई नीति से शिक्षा में लचीलापन आएगा। शिक्षण संस्थाओं में नई व्यवस्था बनेगी, जिसका लाभ लाखों छात्र-छात्राओं को मिलेगा। देश को कुशल और सिद्धस्थ कौशल की प्राप्ति होगी।

खेलो इंडिया योजना

भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी निवास करती है। लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। युवाओं की इसी बड़ी संख्या को देखते हुए, खेलो भारत कार्यक्रम का शुभारम्भ वर्ष 2017-18 में हुआ। योजना का उद्देश्य खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ज़मीनी स्तर के खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना और संपूर्ण भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम में 21 खेलों को शामिल किया गया हैं। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग यानि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान "खेलो भारत" के लिए 3165.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का निर्णय लिया है।

पद्मभूषण श्री देवेंद्र झाझरिया

पैरालंपियन (खिलाड़ी)

श्री देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। देवेंद्र झाझरिया को पद्मभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। झाझरिया कहते हैं कि पहले खिलाड़ियों को कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन जब वह दूसरी बार पदक जीतकर स्वदेश लौटे, तो खेल मंत्री स्वयं स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खेल के क्षेत्र में यह बदलाव विस्मित करने वाला और बेहद सुखद है।

खेलें भी और खिलें भी

सुश्री बबीता फोगाट

महिला पहलवान

दंगल गर्ल सुश्री बबीता फोगाट सुप्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान हैं। बबीता अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में देश के लिए अनेक पदक जीते हैं। बबीता फोगाट मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेलों का स्तर सुधारने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए हैं, जिनके नतीजे भी पदकों के रूप में सामने आ रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

डबल इंजन की सरकार

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। देश के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,वहां तीव्र गति से विकास हो रहा है। डबल इंजन सरकार का अर्थ ही विकास की दोगुनी रफ्तार है। कारण जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होती है, तो जन-कल्याणकारी योजनाएं सरलता और सफलता के साथ लागू होती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच श्रेय लेने की होड़ भी नहीं होती है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश के कुल 28 राज्यों में से 14 राज्यों में बनी हुई है। 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, नगालैंड, पुदुचेरी और सिक्किम में बीजेपी की मिलीजुली सरकार है।

"डबल इंजन सरकार का सीधा और साधारण मतलब है कि विकास की रफ्तार डबल। बीते नौ वर्षों का यही अनुभव रहा है। जहां-जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है,वहां-वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं,जबकि इसके ना होने से जनता पर 'डबल मार' पड़ती है।"

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

“डबल इंजन सरकार डबल रफ्तार”

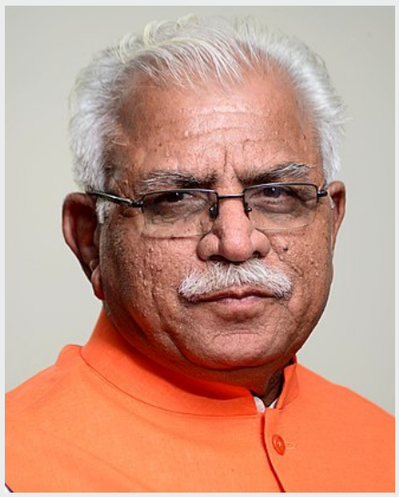

श्री मनोहर लाल खट्टर

मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी संगठन में लंबे समय तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी के रूप में कार्य किया है। आप बताते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हरियाणा ने भी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया है। आपका प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई हर योजना का लाभ पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में भी आपने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है।

उत्तर प्रदेश
उत्तम प्रदेश

उत्तर प्रदेश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। विकास का श्रेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ को जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 'जो कहा, वो करके दिखाया' है। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, एक साल के भीतर उन्हें एक-एक कर पूर्ण कर दिखाया। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया-अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है।

जो कहा, वो करके दिखाया

डॉ. अनिल अग्रवाल

राज्यसभा सांसद

राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल जी के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल अद्भुत रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति चुस्त-दुरुस्त हुई है। प्रशासन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसलिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश को लोग पहले बीमारू राज्य समझते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहां विकास की गति देश में सबसे तेज है। तीर्थ स्थलों के विकास से प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का ग्राफ भी पूरे देश में सबसे ऊपर है।

छत्तीसगढ़ : नक्सलवाद को नकारा

रामायण काल से सत्रहवीं शताब्दी तक कोसल के रूप में जाना जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ आज भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से सशक्त छतीसगढ़ 1 नवंबर सन् 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत में अत्यंत समृद्ध है। यहां की बहुत ही जीवंत संस्कृति है। 36 गढ़ों वाले इस राज्य की संस्कृति यहां के पारम्परिक लोकगीतों एवं लोकनृत्यों में दिखाई देती है।

Chhattisgarh
full of surprises
Chhattisgarh Tourism Board

राजिम कुंभ

“नक्सलवाद को मिटाएंगे, युवा रोजगार पाएंगे”

“छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के लिए काफी अहम हैं। पहले जहां देशभर में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वह घटकर अब 70 रह गई है। केंद्र सरकार नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है।“

– छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री बृजमोहन अग्रवाल

शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में मोहन भैया के नाम से लोकप्रिय श्री बृज मोहन अग्रवाल कहते हैं कि भाजपा सरकार ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को खुले दिल से आर्थिक मदद देती आ रही है। बावजूद इसके पिछले 5 साल में कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल में विकास की गति मंद पड़ गई थी। लेकिन अब फिर से इसे ऊर्जा मिली है क्योंकि मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जो 1 जुलाई 2017 से देशभर में लागू है। वस्तु एवं सेवा कर की दरें तय करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी, कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों (एक ऐसा कर जो आय या मुनाफे के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया हो) को बदल दिया है।

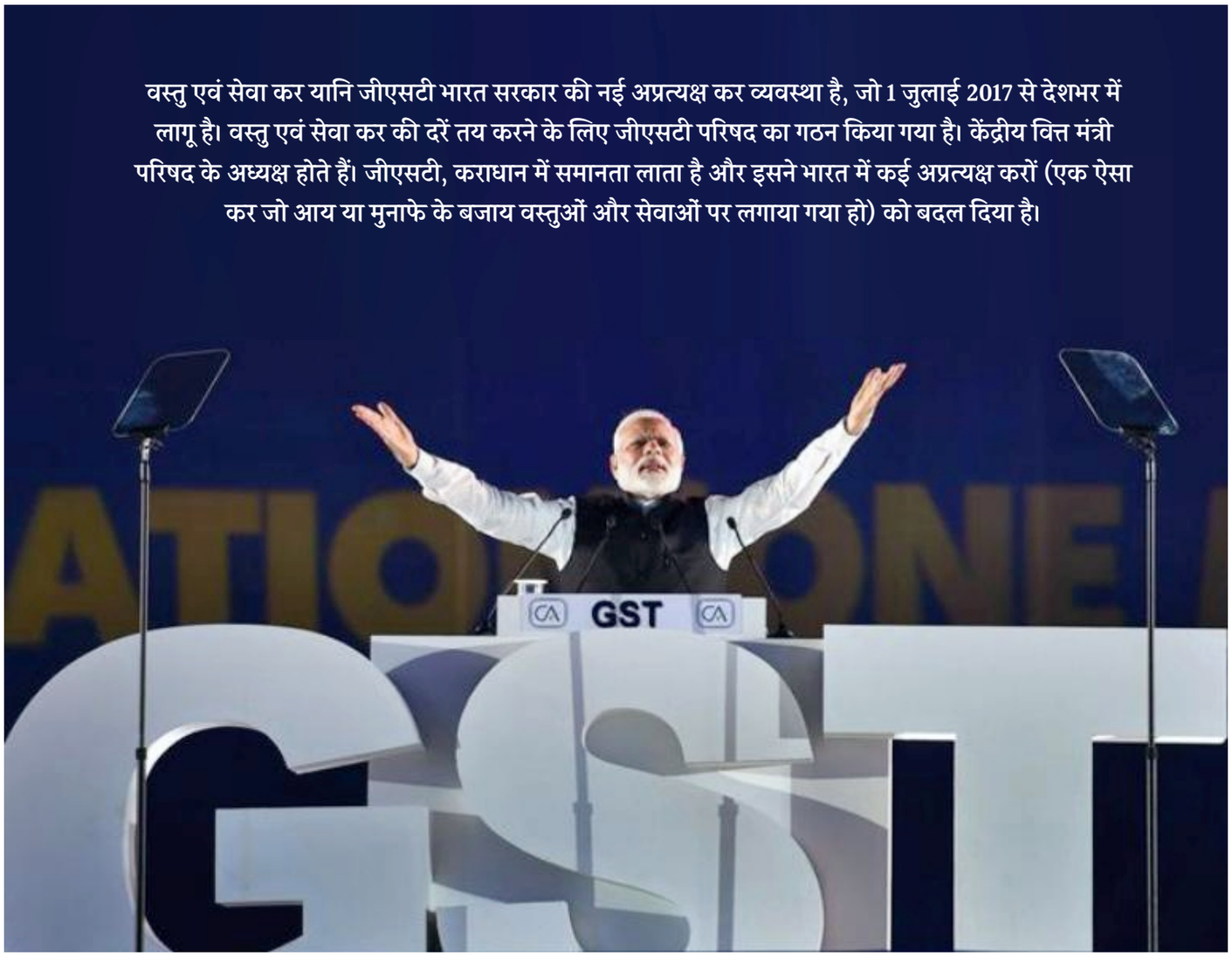

"'भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। निचली कर दरों के बावजूद संग्रह बढ़ना जीएसटी की सफलता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि जीएसटी ने कैसे एकीकरण और अनुपालन को बढ़ाया है।" – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

जीएसटी का कमाल सरकार मालामाल

जीएसटी लागू होने से न केवल व्यापारियों को सुविधा हुई है बल्कि कर चोरी भी रुकी है और सरकार के पास प्रतिमाह डेढ़ लाख करोड रुपए से ज्यादा का राजस्व आ रहा है। जिससे सरकार न केवल कर्ज मुक्त हो गई बल्कि उसका खजाना भी भरा हुआ है और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।

श्री वी. के. गर्ग

पूर्व आईआरएस

श्री वी. के. गर्ग जी 1983 बैच के पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं। 2013 में वीआरएस लेने के बाद कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े टैक्स कंसल्टेंट हैं। 30 साल के अपने करियर में आपने सरकार के लिए कई नीतियां बनाईं और उन्हें सफलता पूर्वक लागू कराया है। जीएसटी नीति ड्राफ्ट में मुख्य भूमिका निभाने वाले गर्ग जी कहते हैं कि जीएसटी लागू करना आर्थिक सुधार की दिशा में आजादी के बाद का सबसे बड़ा कदम है। इससे कर चोरी रुकी है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जीएसटी से प्राप्त होने वाले धन को सरकार चहुंमुखी विकास के कार्यों में खर्च कर रही है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

नागरिकता संशोधन अधिनियम

नागरिकता संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद देश भर में लागू कर दिया है। यह लोकसभा में 10 दिसंबर तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आकर रहने वाले अफ़गानिस्तानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इससे पूर्व नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 में प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था,जिसे घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः,सर्वे सन्तु निरामया”

“नागरिकता संशोधन कानून को देश की संसद ने दलितों और शोषितों के उज्जवल भविष्य के लिए पारित किया है। आप खड़े होकर देश की जनता के चुने हुए सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा का सम्मान कीजिए। मैं भी आपके साथ जुड़ करके देश के सर्वोच्च सदन और उनके जनप्रतिनिधि का सम्मान करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। मैं नागरिकता संशोधन कानून पास करने के लिए संसद को प्रणाम करता हूं।”

-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग

पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश जस्टिस मूलचंद गर्ग जी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरी तरह से संविधान सम्मत है। यह किसी को डराने के लिए नहीं है,क्योंकि इसमें किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अत्याचार और उत्पीड़न से परेशान जो लोग हिन्दुस्तान में आए हैं, उन्हें नागरिकता देकर शांति का जीवन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी को दोनों सदनों में इसे पारित करवाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज़ापित करता हूं।

धारा 370 का समापन

दूर हो चुका है डल झील का सूनापन

धरती की जन्नत वही है, बस माहौल और मिजाज बदला हुआ है। ये बदला-बदला कश्मीर है। बहारों ने कश्मीर की बेड़ियां तोड़ दी है। चहुंओर शांति है। लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। घाटी में पत्थरबाजी पर पाबंदी लग चुकी है। अब बाजार बंद नहीं होते। परिवहन की व्यवस्था में रुकावट नहीं आती। पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ गई है। डल झील का सूनापन दूर हो चुका है।

धारा 370 को हटाना बीजेपी सरकार के तीन बड़े चुनावी वादों में से एक था। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को समाप्त कर, वहां दो केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। जम्मू कश्मीर सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी, जिसके कारण कई भारतीय कानून वहां लागू नहीं थे। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान और एक प्रधान का नारा देते हुए धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया था।

"कश्मीर को लेकर हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, वह पूरी तरह से घरेलू मामला है। हमने इस निर्णय को काफी सोच-समझ कर लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि इससे घाटी के लोगों को काफी फायदा होगा।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पांगोंग झील लद्दाख

सोनमर्ग कश्मीर में तिरंगा

श्री मंजूर भट

युवा नेता, जम्मू-कश्मीर बीजेपी

मंजूर भट जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के युवा नेता हैं। मंजूर जी का मानना है कि आज कश्मीर के घर-घर में तिरंगा लहरा रहा है और मोदी जी के मार्गदर्शन में अपने खोए हुए वैभव को फिर से प्राप्त कर रहा है। राज्य में शांति स्थापित हुई है और लोगों का विश्वास लौटा है। आज पूरे क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ी है।

एक देश एक संविधान

लेह लद्दाख

श्री महबूब अली खान

पर्यटन सचिव, लेह-लद्दाख

केंद्र शासित प्रदेश लेह-लद्दाख के पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव महबूब अली खान का कहना है कि जम्मू-कश्मीर तथा लेह-लद्दाख क्रमशः चीन और पाकिस्तान के साथ एलएसी और एलओसी पर पड़ता है। पहले ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए खुले नहीं थे और उन्हें परमिट की आवश्यकता थी। परंतु 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख ने घरेलू पर्यटकों के लिए परमिट प्रणाली को हटा दिया। कुछ स्थानों को छोड़कर यहां पर्यटकों की आवाजाही निःशुल्क है। सामरिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब शांति स्थापित हुई है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

“पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है”

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति और सैन्य शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर बालाकोट और पीओके के आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाना, विंग कमांडर अभिनंदन की 56 घंटे के अंदर सकुशल वतन वापसी और पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, जैसे मुद्दों पर सभी प्रमुख वैश्विक नेताओं का भारत के साथ एकजुटता में खड़े रहना, इनके उदाहरण हैं। भारत आज पीओके को वापस लेन की अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ता पर अडिग है, तो यह प्रधानमंत्री की कूटनीतिक पहल और दुनिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का ही प्रतिफल है।

“हमारी सरकार कश्मीर में अशांति का स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का अभिन्न हिस्सा है।”
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
(12 अगस्त 2016 को कश्मीर मसले पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में)

जनरल डी.पी. वत्स

राज्यसभा सांसद एवं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल

श्री डी.पी. वत्स का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आज न कल भारत में शामिल होगा, क्योंकि यह वहां के लोग भी चाहते हैं। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति, लोगों में फैली भूखमरी, उनका बगावती रुख और सरकार के प्रति क्रोध उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक को जहां भारत सरकार का आवश्यक और साहसिक कदम बताते हैं, वहीं विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी का श्रेय सफल भारतीय कूटनीति और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को भी देते हैं।

कोरोना महामारी

“कोरोना के विरुद्ध, जीता युद्ध”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी जैसे महासंकट में न केवल देश, बल्कि दुनियाभर के लोगों के लिए भी काम किया। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात् दक्षेस के सदस्य देशों के साथ संपर्क-संवाद कायम कर अपनी नेतृत्व क्षमता, उदारता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। संकट से निपटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाली पहल की। सार्क देशों के बीच भारत एक नई उम्मीद बनकर उभरा। इन उजालों को निर्मित करने में प्रधानमंत्री की मानवतावादी सोच और सूझबूझ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डॉक्टर अनिल अग्रवाल

हृदय रोग विशेषज्ञ एवं प्रांत संघचालक

डॉक्टर अनिल अग्रवाल सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। एक एलोपैथिक सर्जन होने के बावजूद आयुर्वेद पर आपका दृढ़ विश्वास है। आपका मानना है कि आयुर्वेद और अंग्रेजी पद्धति दोनों वैज्ञानिक हैं। दोनों के अपने-अपने स्थापित नियम हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का योगदान किसी भी सूरत में एलोपैथी से कम नहीं है। लाखों रोगी आयुर्वेद की दवाइयां लेकर और उसके नियमों का पालन करके रोगमुक्त हो रहे हैं। आप आयुर्वेद में और अधिक शोध करने की वकालत करते हैं।

"दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी कोरोना से लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा। कोरोना के काल में जिन लोगों ने अपने परिजन और परिचितों को खोया, उनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। ये बीते 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी महामारी है, जिससे हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

ब्राजील के राष्ट्रपति का ट्वीट

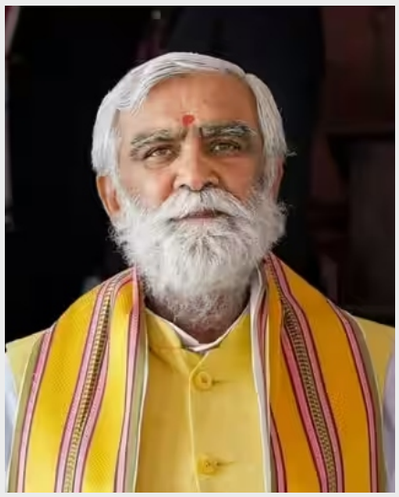

श्री अश्विनी चौबे

केंद्रीय राज्य मंत्री, पर्यावरण एवं खाद्य आपूर्ति

केंद्रीय पर्यावरण एवं खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी का कहना है कि कोरोना महामारी हमारे देश के लिए एक अभिशाप था। लेकिन माननीय मोदी जी के "मेक इन इंडिया" विजन से इस महामारी में एक सकारात्मक स्थित में आए। जहां देश में पीपीई किट, एन-95 मास्क और टेस्टिंग लैब जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, वहां मोदी जी ने अपने संकल्प, कौशल और दृढ़ निश्चय से ना केवल कोराना की दवाई बनवाने में सफलता अर्जित की, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी आपूर्ति कर करोड़ों लोगों का जीवन बचाने का कार्य किया।

राष्ट्र प्रथम

मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित।
चाहता हूँ मातृ-भूमि तुझको अभी कुछ और भी दूँ।।

प्रधानमंत्री का लोकतंत्र के मंदिर को नमन

“प्रथम राष्ट्र नो कॉस्ट”

‘ये हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध, देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हो सकती हैं। लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। राष्ट्र प्रथम है।’

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा **"राष्ट्र प्रथम"** का दिया गया नारा आज जन-जन की आवाज बन गया है। भारतवासी इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि मान रहे हैं। भारतवर्ष की गौरव गाथा गा रहे हैं। देश के युवा राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभा रहे हैं। देश की आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। राष्ट्र रक्षा में सीमाओं पर बलिदान देने को तत्पर हैं। देशवासियों का मानना है कि हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। हमारा कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, सुंदरता और निर्माण होना चाहिए। प्रत्येक सुबह राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पूर्व हमारे मन में राष्ट्रप्रेम की भावना होनी चाहिए। आने वाले 25 साल में हमें इन पांच प्राण तत्वों को केंद्र में रखकर काम करना है। ये पांच प्राण तत्त्व हैं – विकसित भारत, गुलामी की रंच मात्र सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों के कर्तव्य।

श्री लक्ष्मी नारायण भाला

वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

लक्ष्मीनारायण भालाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। पिछले 55 साल से आप समाज सेवा में जुटे हैं। आप लेखक और कवि भी हैं। आपने विभिन्न सामाजिक विषयों पर कई पुस्तकों का लेखन किया है। आप हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सह-संयोजक हैं।

भाला जी के भाव

देह-तत्व से देव-तत्व तक, यात्रा में है एक पड़ाव।
देश-तत्व के इस पड़ाव में, देश-प्रथम हो मन का भाव।।

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

"स्वच्छ भारत अभियान" जिसे "स्वच्छ भारत मिशन" के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार के द्वारा शुरु किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक स्वच्छता अभियान है, जिसका उद्देश्य अधारभूत संरचनाओं तथा सड़कों, नदियों और गलियों आदि को साफ-सुथरा करना है। इस अभियान का शुभारंभ महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को किया गया।

'ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे।'

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“जन-जन का एक ही सपना, कचरामुक्त हो भारत अपना”

प्रधानमंत्री श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए

विनम्र श्रध्दांजलि

“15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बीच, इस खबर को आत्मसात कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि बिंदेश्वर पाठक जी हमारे बीच नहीं रहे। सहज, सरल, विनम्र व्यक्तित्व के धनी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर जी का जाना एक अपूरणीय क्षति है। स्वच्छता को लेकर उनमें जो जज्बा था, वो मैं तब से देखता आ रहा हूं, जब मैं गुजरात में था।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पद्म विभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक

संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल

सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म विभूषण स्व. डॉ. बिंदेश्वर पाठक जी का मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जागृत करने का कार्य किया है। घर-घर शौचालय निर्माण करवाया। स्वच्छाता का बजट अनुदान बढ़ाया। आपके अनुसार हर बड़ी कंपनी कम से कम 1 जिले को गोद लेकर कार्य करे। देश में कम से कम 1000 बड़ी कंपनियां हैं। 1 जिले को पूरी तरह स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए 600 करोड़ का बजट पर्याप्त है। देश में कुल 670 जिले हैं। विदेशों में बसे भारतीयों की संख्या 2 करोड़ है। प्रत्येक एनआरआई को चाहिए कि वो 6 शौचालय गोद ले। पंचायत स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाए।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारत की बेटियां आज आजाद हैं। सुखी हैं। संपन्न हैं। खुशहाल हैं। विकासोन्मुख हैं। बेटियां शिक्षित हो रही हैं। सशक्त हो रही हैं। आत्मनिर्भर बन रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सेना तक में अपना कौशल दिखा रही हैं। घर में, परिवार में, समाज में, रोजी में और रोजगार में भी अपने हुनर से सब का दिल जीत रही हैं। वास्तव में 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया गया महाअभियान "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" अपना रंग दिखा रहा है। अभियान का शुभारंभ ही महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान और महिला उत्थान के साथ-साथ लिंगानुपात संतुलन बनाने, बालिकाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और उनकी शिक्षा-दिक्षा सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज लिंगानुपात में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और भारत की स्थिति 8 पायदान ऊपर आई है।

"आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप पांच पेड़ लगाएं।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे ?

साध्वी ऋतंभरा जी

संस्थापक, परम शक्ति पीठ वृंदावन

साध्वी ऋतंभरा जी ने नारी निकेतन, वृद्धाश्रम एवं अनाथालय की पूरक व्यवस्था स्वरूप वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। कन्याभ्रूण उन्मूलन हेतु व्यापक अभियान भी चलाया। आप अपने शिष्यों से दक्षिणा में कन्या भ्रूण संरक्षण का वचन लेती हैं। आपका मानना है कि "कन्याभ्रूण संरक्षण" तथा "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का नेक कार्य समाज को अपने हाथों में लेना होगा। देश के लिए प्रधानमंत्री जी के दिल में जो दर्द है, वही दर्द सरकारी और सामाजिक तंत्र में जागना आवश्यक है। क्योंकि सरकारी मशीनरी, मशीन की तरह काम करने की आदि होती है।

सशक्त सेना सशक्त भारत

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारतीय सेना का बजट भी बढ़ाया जा रहा है। अब हम ना केवल हथियार बनाने लगे हैं, बल्कि इसका निर्यात भी करने लगे हैं। मोदी जी सीमा पर सैनिकों के बीच दिवाली मनाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है।

वन रैंक वन पेंशन

"वन रैंक वन पेंशन' मेरे लिए आस्था का विषय"
– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

लेपचा में सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री की दिवाली

कर्नल टी. पी. त्यागी (सेवानिवृत)

वीर चक्र से अलंकृत

भारत-पाक युद्ध के हीरो कर्नल टीपी त्यागी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना को एक नई ऊंचाई और गौरव प्रदान किया है। आज की सेना पूरी तरीके से सुसज्जित है। किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है। सेना के पास सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार हैं। बचाव की मुद्रा में रहने वाला हिन्दुस्तान अब आक्रामक मोड़ में आ गया है। हम ब्रहमोस और तेजस का निर्यात भी कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कारिडोर बन गए हैं। देश तकनीकी समझौते करने लगा है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। परियोजना का उद्देश्य गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर अंग्रेजी दवाइयां उपलब्ध करवाना है। जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। जन औषधि केंद्रों से होने वाली दवा की बिक्री पर केंद्र संचालकों को 20 प्रतिशत कमीशन भी दिया जाता है। सरकार केंद्रों को जेनरिक दवाओं की लगातार आपूर्ति बनाए रखती है।

"देश के गरीब और मध्यम वर्ग को ये विश्वास हुआ है कि सरकार उन्हें उत्तम, सस्ता और सुलभ इलाज देने में जुटी है। इससे अपेक्षा जितनी बढ़ी है, उतने ही हमारे प्रयास भी व्यापक हो रहे हैं।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“सस्ती और असरदार दवाएं”

श्री रवि दाधीच

सीईओ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

श्री रवि दाधीच दिल्ली कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप पिछले 2 से अधिक वर्षों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। श्री दाधीच के अनुसार सरकार ने निकट भविष्य में देश भर में 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 9500 खुल चुके हैं। इन केंद्रों पर 2000 प्रकार की दवाइयां और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जो बाजार के मुकाबले 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ते हैं। सरकार की इस योजना का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

आयुष्मान भारत

जीवन में चाहे जितनी धन-संपत्ति हो,स्वास्थ्य साथ न दे,तो वो किसी काम के नहीं। इसलिए कहा जाता है "स्वास्थ्य ही जीवन है", “स्वास्थ्य ही धन” है। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी होता है,संयम रखना, खान पान पर नियंत्रण करना और रोग होने पर समय रहते उपचार मिलना। 01 अप्रैल 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ भी इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु हुआ है।

योजना का प्रयोजन बीपीएल कार्डधारकों के 10 करोड़ परिवरों के 50 करोड़ सदस्यों को आयुष्मान भारत कार्ड के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। योजना के दायरे में देश की कुल आबादी के 40 प्रतिशत लोग आते हैं। ये वे गरीब लोग हैं, जो स्वयं से स्वास्थ्य योजना लेने की स्थिति में नहीं है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है।

“आयुष्मान भारत ने हमारे गरीब भाई-बहनों के इलाज के खर्च की चिंता दूर की है। यह योजना जिस तरह से उनके लिए रक्षा कवच बनी है, वो किसी वरदान से कम नहीं है।”

– प्रधानमंत्री जी का ट्वीट (7 अप्रैल 2023)

"स्वास्थ्य ही जीवन है"

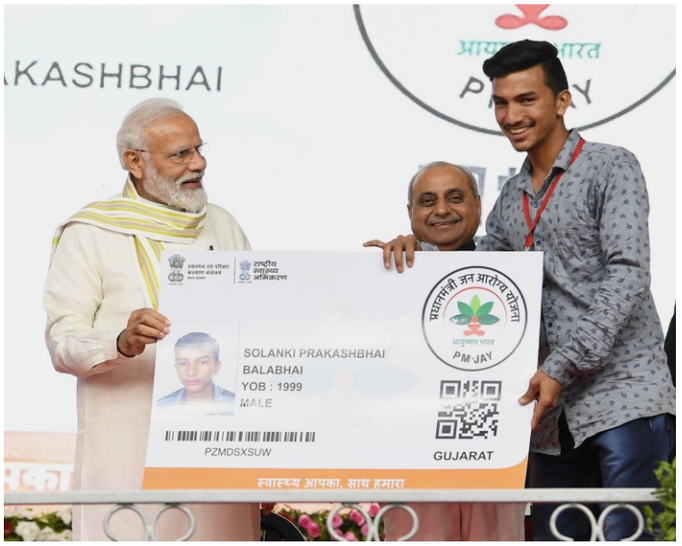

डॉक्टर (प्रो.) जी. के. रथ

कैंसर विशेषज्ञ, एम्स

डॉक्टर जी.के. रथ जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ हैं। आपने 40 से भी अधिक वर्षों तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में अपनी सेवाएं दी है। देश-विदेश में कई कैंसर संस्थानों की स्थापना में अभिदान देने वाले डॉक्टर साहब का मानना है कि आयुष्मान भारत जैसी योजना से गरीबों का जीवन बदल गया है। देश के सभी राज्यों में एक एम्स खोलने की जो पहल की गई है, वह प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच और संवेदनशीलता का परिणाम है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लगने वाले बजट को भी बढ़ाया है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

श्रीराम मंदिर निर्माण

“प्राण प्रतिष्ठा से राष्ट्र प्रतिष्ठा”

पांच शताब्दियों की लंबी प्रतीक्षा के उपरांत 22 जनवरी 2024 को वह ऐतिहासिक पल आ गया जब भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदू पक्ष में निर्णय देने के पश्चात 05 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी देश-विदेश के 10 हजार से अधिक रामभक्त और अतिथि बने।

"ये मंदिर, मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है. ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है. राम भारत की आस्था हैं, राम भारत का आधार हैं।

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

बालक राम

"एक तीर्थस्थल से बढ़कर है श्रीराम मंदिर की महत्ता"

'जब श्रीराम का अभिषेक होता है, तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श व मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया गया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। आजादी के इस अमृतकाल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में, जिन मूल्यों को गढ़ा वो सबका साथ-सबका विकास की प्रेरणा हैं और सबका विश्वास-सबका प्रयास का आधार भी है।'

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री मिलिंद परांडे

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद

श्री मिलिंद परांडे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। आप आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक होने के साथ-साथ धर्म जागरण के कार्य में भी संलग्न हैं। आपको विश्वास है कि प्रभु श्री राम का मंदिर राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय स्वाभिमान को जाग्रत करने का कार्य करेगा। विश्व हिन्दू परिषद के अनुसार अब काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण जन्म भूमि को मुक्त कराना भी हिंदू समाज की कार्य सूची में है।

रामवन गमन मार्ग

चैतन्य की पराकाष्ठा के स्वामी, धैर्य और प्रेम के स्वरुप श्रीराम जी ने सम्पूर्ण धरातल जगत को मातृ एवं पितृ भक्ति, भ्रातृ स्नेह, प्रकृति में समाहित कण - कण में जितने भी जीव हैं, उनके प्रति अपार स्नेह व मर्यादा का ज़ान प्रदान किया है। उन्ही प्रभु श्रीराम के वन गमन मार्ग के सभी तीर्थस्थलों को सम्पूर्ण भारत के लोगों से जोड़ने हेतु केंद्र सरकार ने "स्वदेश दर्शन योजना" के अंतर्गत रामायण परिपथ परियोजना का श्रीगणेश किया है। रामायण परिपथ में देश के 9 राज्यों के 15 स्थानों को सम्मिलित किया गया है। योजना का उद्देश्य उन सभी स्थानों को जोड़ना है, जहां-जहां भगवान श्रीराम गए और जो रामायण से जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। शोधकर्ता डॉ. रामावतार शर्मा (अध्यक्ष - श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास) के द्वारा श्रीराम वन गमन मार्ग पर 40 वर्षों का शोध कार्य कर 290 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों पर अशोक सिंहल फाउण्डेशन एवं M2K फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में विशाल, अद्भुत और अनूठे श्रीराम स्तम्भों की स्थापना करने का संकल्प लिया गया है।

श्रीराम स्तम्भ

न्याय व्यवस्था

भारतीय न्यायपालिका को दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक माना जाता है,जो भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह भारत के नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परंतु मामलों का अनिर्णित रहना एक बड़ी समस्या है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 4 करोड़ मामले अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बैकलॉग क्रमशः 43 लाख और 57,987 मामले हैं। यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो अदालतों की अपर्याप्तता को दर्शाता है। न्यायाधीशों की संख्या भी कम है। इसलिए कॉलेजियम प्रणाली खत्म कर, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है।

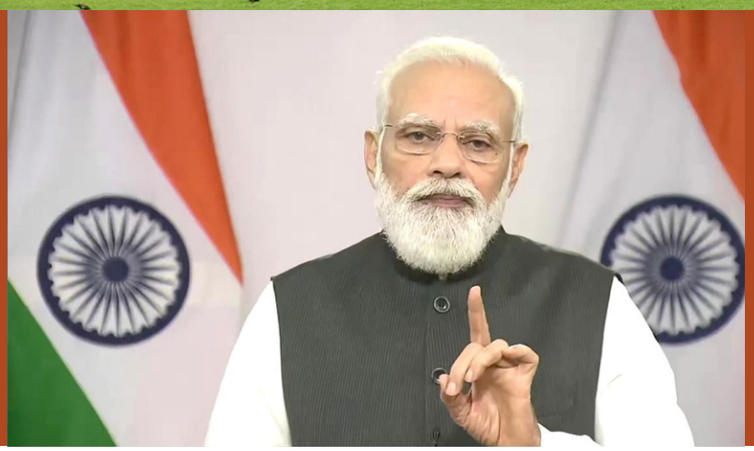

"स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्यायपालिका का होना जरूरी है। न्याय मिलने में देरी देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

न्याय की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति

एक जमाना था जब न्यायालयों में आरोपी के हाथ में गीता देकर सच बोलने की शपथ दिलवाई जाती थी। अभी न्यायालयों में लगी न्याय की देवी के साथ संविधान की पुस्तक रखी गई है। कुछ न्यायधीशों का सुझाव है कि न्याय की देवी के साथ तीन ग्रंथ वेद, पुराण और गीता भी रखे जाने चाहिए। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल कहते हैं कि न्याय करते समय भारतीय परिपेक्ष को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय परिपेक्ष का अर्थ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं में दिए गए जीवन मूल्य हैं। जिसका मूल आधार वेद, पुराण और गीता ही हैं।

श्री आदीश अग्रवाल

अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

श्री आदीश अग्रवाल देश के जाने-माने अधिवक्ता और इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेखन में भी आपकी रुचि है। देश के कई प्रधानमंत्रियों पर आपने पुस्तकें लिखी हैं। आप बेबाकी से कहते हैं कि न्याय में देरी के लिए काफी हद तक न्यायाधीश भी दोषी हैं, क्योंकि कॉलिजियम व्यवस्था से जजों की नियुक्ति की शक्ति होने के बावजूद पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

समाज कल्याण नीति

नर सेवा ही नारायण सेवा है। इससे बड़ा न तो कोई धर्म है और ना ही पवित्र कार्य है। गरीबों, बेसहारों, असहायों, निशक्तों और जरूरतमंदों की सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। निःस्वार्थ सेवा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। युग-युगांतर से प्रचलित वाणी "सेवा परमो धर्मः" को आत्मसात कर उसे चरितार्थ करने वालों को ही भविष्य में महामानव की उपाधि मिलती है। सेवा चाहे मातृभूमि की हो, माता-पिता की हो, मानव जाति की हो या जीव-जंतुओं की हो, इनकी सेवा से धर्म की प्राप्ति और आत्म संतुष्टि के बीच जीवन भी सफल होता है।

"भक्तिमार्ग से भी ऊँचा है सेवामार्ग" | "नर सेवा,नारायण सेवा" | "सेवा ही सर्वोत्तम धर्म"

"मानवीय दृष्टिकोण, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच एवं उनसे जुड़ाव और सेवा करने की अनुपम मानसिकता, जिसकी बदौलत लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं।"

– स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी के उद्गार

डॉक्टर बी. एम. भारद्वाज

संस्थापक, अपना घर आश्रम

"अपना घर आश्रम" के संस्थापक डॉक्टर बी. एम. भारद्वाज दंपत्ति ने आजीवन निःसंतान रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली है। बेसहारा और असहाय लोगों की सेवा ही इनका परम धर्म है। अब तक 35 हजार से अधिक बेसहारा लोगों का उपचार कर उन्हें, उनके परिजनों से मिलवा चुके डॉक्टर साहब कहते हैं कि लावारिस गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए देश में कोई केंद्र नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो परिवार से त्यागे गए असाध्य रोगियों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए कानून बनाए। क्योंकि सरकारी अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नीतियां बनाते हैं, जो धरातल पर नहीं उतर पातीं।

अद्वितीय संसदीय कार्य

केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद में काम करने की शैली को परिवर्तित करने का कार्य किया है। बजट को 28 की बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। संसद की कार्यवाही देर रात तक चलाई गई और संसदीय कार्य पूरे किए गए। मोदी जी ने सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों की उपस्थिति में भी विशेष बढ़ोतरी देखी गई है।

“संसद के दोनों सदनों में अभूतपूर्व कार्य”

“बीते दिनों इसी संसद के दोनों सदनों ने जन विश्वास बिल,मीडिएशन बिल, डेंटल कमिशन बिल, आदिवासियों से जुड़े बिल, डिज़िटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल देश की युवा शक्ति की आशा और आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज़्बे में जो बात प्रमुखता से है, उससे जुड़ा है। आने वाला समय तकनीक से चलने वाला है।”

–प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए)

श्री अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री

केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संसद के दोनों सदनों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सदन में सांसदों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही, संसद का कार्य देर रात तक चला और सदन की बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, कार्यकुशलता और फ्लोर मैनेजमेंट को जाता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

“जिनकी मेहनत देश का आधार,उनकी पेंशन का सपना साकार”

देशभर में 15 फरवरी 2019 को “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” लागू की गई। आज योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के साथ ही सब्जी बेचने वालों, चाय बेचने वालों, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वालों, भट्टा कर्मकार और दिहाड़ी मजदूरों को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने दी जाएगी। योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति को प्रत्येक महीने 55 रुपए निवेश करने होते हैं। आयकर दाता इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।

“मैं गरीबों और श्रमिकों का दर्द समझता हूं, मैंने अनुभव किया है कि एक उम्र के बाद जब शरीर काम नहीं कर पाता तब किस स्थिति में जीवन गुजारना पड़ता है। इस हालत में कोई साथ नहीं देता, वे अपने भी साथ छोड़ देते हैं जिनके लिए आपने पूरा जीवन खपा दिया।”

– –प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम”

“भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें सफलता भी मिली है लेकिन हम इतने से संतोष नहीं मान सकते। मेरे देशवासियों पर महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में मुझे और भी कदम उठाने हैं और मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री पवन कुमार

संगठन मंत्री (उत्तर मध्य क्षेत्र), भारतीय मजदूर संघ

श्री पवन कुमार जी बताते हैं कि बीएमएस एक गैर राजनीतिक संगठन है और श्रमिकों के विरोध में कार्य करने वाली किसी भी सरकार का पुरजोर विरोध करता है। बीएमएस के द्वारा श्रमिकों को स्वावलंबी बनाने और देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। श्रमिकों के हित में कार्य करने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया जाता है। आपका ध्येय वाक्य “देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम” है। आपका मानना है कि राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकिकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना

देश की गरीब जनता को एक अदद आशियाना देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वकांक्षी सपना है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का ताना-बाना बुना गया। योजना की घोषणा 25 जून 2015 को की गई। उद्देश्य गरीबों को अपना आशियाना (पक्का घर) उपलब्ध कराना है। सरकार गरीबों को उनका घर बनाने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। 2023-24 में इस योजना का बजट 66 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

जन-जन का सपना, एक घर हो अपना

"पीएम आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिल चुका है। सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि सरकार जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं के जरिए देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के ईमानदार प्रयास कर रही है।"

– एक लाभार्थी सुधीर जैन को लिखे अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल 2022

श्री प्रदीप अग्रवाल

सीएमडी, सिग्नेचर ग्लोबल

श्री प्रदीप अग्रवाल जी का कहना है कि केंद्र सरकार की पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। आयकर में दी जा रही छूट का लाभ घर खरीदारों को मिल रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वह बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स को सस्ते मकान बनाने के लिए प्रेरित करे। ब्याज दरें कम की जाएं। राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम बनाई जाए। 9 साल में चार करोड़ से अधिक पक्के मकान बने हैं,जिनमें 70 प्रतिशत महिलाओं को मिले हैं।

कृषि नीति एवं कृषि कानून

समृद्ध किसान, सशक्त राष्ट्र

"अन्नदाता सुखी भव:" – किसानों के प्रति पीएम के उद्गार

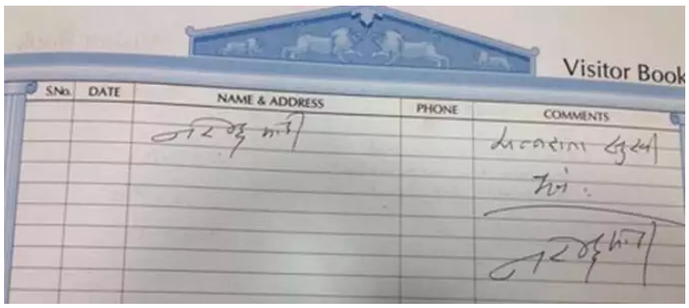

"पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत दो चीजों को दिखाता है। किसानों के कल्याण के प्रति राजग की अटूट प्रतिबद्धता एवं तेज निर्णय की प्रक्रिया। 1 फरवरी को घोषित योजना इतने कम समय में हकीकत का रूप लेने जा रही है। यह नए भारत की नई कार्य संस्कृति है। यह योजना इसी वित्त वर्ष से ही लागू हो गई है और यही वजह है कि किसानों को मार्च आखिर तक दो हजार रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी। यह योजना कृषि क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने की केंद्र सरकार की कोशिश का हिस्सा है।"

–प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

देश के किसानों को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योजना का शुभारम्भ किया। कोरोना काल में इससे किसानों को काफी मदद मिली। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों को वर्षभर में 6,000 रुपए की सहायता देती है। किसानों को दो-दो हजार की किस्त में पैसे मिलते हैं। इसमें जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए पात्रता तय की जाती है। इसके अलावा करीब 3 करोड़ किसानों को कर्ज पर 3 महीने के मोरेटोरियम का लाभ भी दिया गया है।

श्री नरेंद्र सिंह तोमर

तत्कालीन केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री

श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के अनुसार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए 201 सुझाव दिए, जिनमें से 200 सुझावों को माननीय मोदी जी ने लागू कर दिया है। सबसे प्रमुख सुझाव यह था कि किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम मिले,जिसे क्रियान्वित करने का साहस अगर किसी ने दिखाया है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में लॉकडाउन, कोरोना महामारी और तीन कृषि कानूनों का विरोध ने रोड़ा अटकाने का काम किया।

"मैं देशभर के किसानों को बधाई देता हूं। पहले किसानों के लिए योजनाएं बनीं, लेकिन उनकी मंशा किसानों को सशक्त करने की नहीं थी। किसानों को तरसाने की नीयत थी। इसी स्थिति को बदलने के लिए हमने किसानों की दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही चुनौतियों से निपटने पर भी ध्यान दिया है"

–प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पद्मश्री कमल सिंह चौहान

किसान नेता

पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी तीन कृषि कानून पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। आपका कहना है कि कुछ बदलाव के बाद कानूनों को लागू करना किसानों के हित में होता। परंतु राजनीतिक दलों और किसानों के विरोध के कारण यह हो नहीं सका। आप खेती को व्यापार की तरह करने की प्रेरणा देते हैं। युवाओं से आप सरकारी नौकरी की बजाय खेती करने का आह्वान करते हैं। आपके अनुसार आधुनिक और बेहतर प्रबंधन के साथ खेती की जाए,तो इसमें बहुत लाभ मिल सकता है।

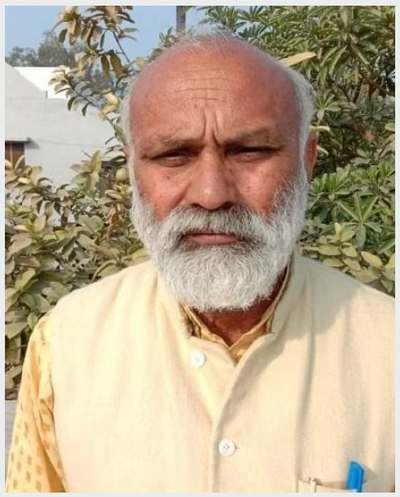

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारम्भ वर्ष 2020 में हुआ,जो वर्तमान में भी संचालित है। योजना के 80 करोड़ लाभार्थियों को 5-5 किलों गेहूं अथवा चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित हुआ,जिसके कारण कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए। दिहाड़ी मजदूरों को दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे विकट समय पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। आठवें चरण में इसे 1 फरवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गरीब और पात्र परिवार 2024 तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

"सबको राशन, मुफ्त राशन"

श्री कैलाश चौधरी

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री

श्री कैलाश चौधरी राजस्थान के बाड़मेर से सांसद हैं। आप केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री हैं। आप राजस्थान में किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपका कहना है कि सरकार किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए कृतसंकल्प है,जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयासों में एफपीओ का गठन भी शामिल है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

प्रेस की स्वतंत्रता
(प्रेस परिषद)

किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रेस का स्वतंत्र होना आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहिया है। स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, प्रेस लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। प्रेस सत्ता में बैठे लोगों पर नज़र रखती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इसका दुरुपयोग न करें। प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था।

'मीडिया का काम बेजुबानों को जुबान देना है। एक स्वतंत्र प्रेस एक जीवंत लोकतंत्र की नींव है। हम सभी प्रकार से प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सत्यमेव जयते
भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

प्रधानमंत्री जी के साथ अतुल सिंघल

"पत्रकारिता कोई पेशा नहीं, यह जनसेवा का माध्यम है"

प्रो. के.जी. सुरेश, कुलपति

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

प्रो. के.जी. सुरेश एक वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, शिक्षाविद्, सामाजिक व राजनीतिक टिप्पणीकार और संचार रणनीतिकार हैं। आपका कहना है कि प्रेस परिषद अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है। इसलिए प्रेस परिषद को भंग करके एक ऐसी निष्पक्ष काउंसिल का गठन किया जाए, जो पत्रकारों को लाइसेंस देने का कार्य करे और उनपर नियंत्रण रखे। बार एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल की तर्ज पर।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

नोटबंदी

प्रधानमंत्री जी द्वारा नोटबंदी के जो लक्ष्य तय किए गए थे,वो लगभग सारे पूरे हो गए हैं। आज अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हुई है। सरकार को अधिक राजस्व मिला है। गरीबों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हुए हैं। बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है। नोटबंदी का लक्ष्य था,काले धन को बाहर निकालना, नकली नोटों को बंद करवाना, आतंकवाद की कमर तोड़ना, कर चोरी करने वालों को पकड़ना, भ्रष्ट अधिकारियों के बीच भय उत्पन्न करना और पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा थमाना। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर 2016 की रात्रि 8 बजे पूर्ण नोटबंदी की घोषणा की, जिसे सर्वोच्च अदालत ने भी हाल ही में सही ठहराया है।

“नोटबंदी का हर लक्ष्य हुआ पूरा, आतंकवाद पर लगी लगाम”

"भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए। आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर.. देश जो सजा देगा वो सजा भुगतने को तैयार हूं।"
-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

स्व. श्री सुदर्शन जैन

व्यवसायी एवं समाजसेवक

गौसेवा से गोविंद की और जनसेवा से जनार्दन की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले जैन साहब के अनुसार काले धन पर रोक लगाने और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी एक आवश्यक कदम था। नोटबंदी के दूरगामी लाभ हो रहे हैं। नोटबंदी से व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान तो हुआ है, तब भी नोटबंदी का समर्थन किया जाना चाहिए। सरकार लोगों को इसके प्रति जागरूक करे, सबके बैंक खाता खुलवाए। नकद लेन-देन पर भी रोक लगनी चाहिए।

स्टार्टअप भारत–स्टैंडअप भारत

"स्टार्टअप भारत स्टैंडअप भारत" युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए चलाया गया अभियान है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से की। 16 जनवरी 2016 को योजना का औपचारिक शुभारम्भ हुआ और आज प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 9 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। देशभर में 88 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं।

"आज भारत के युवा नए स्टार्टअप शुरू करके दुनिया को हैरान कर रहें हैं। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है और एक्सपोर्ट नई बुलंदियां छू रहा है, लेकिन विपक्ष भारत की कोई अच्छी बात नहीं सुन सकता है।"
-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री मोहित राय गोयल

युवा उद्यमी

श्री मोहित राय गोयल ने यूके से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया और मोटिफ इलेक्ट्रिक लि. में बिजनेस हेड की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन मोदी सरकार की "स्टार्टअप इंडिया" से प्रभावित होकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। मोहित जी का मानना है कि ये योजना बहुत अच्छी है। भारतीय युवाओं में असीमित प्रतिभाएं हैं। लेकिन एक अच्छा स्टार्टअप शुरू करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऋण लेने के नियमों को और अधिक सरल किया जाना चाहिए। साथ ही स्टार्टअप के लिए सरकार ने जो बजट प्रावधान किए हैं, उनको बढ़ाना चाहिए।

#startupindia

“स्टार्टअप नए भारत की "रीढ़" और इंजन हैं, जो देश की आज़ादी के 100 वें वर्ष के उपलक्ष्य में आर्थिक वृद्धि को शक्ति देगा।”
– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री अरविंद कुमार

महानिदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

श्री अरविंद कुमार का कहना है कि स्टार्टअप इंडिया युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है। यह देश में नवाचार के माध्यम से स्थाई आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। सॉफ्टवेयर सर्विस के निर्यात में भारत अग्रणी है। सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में यहां असीम संभावनाएं। 76 हजार स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में आईटी इंडस्ट्री का योगदान उल्लेखनीय है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना भी सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

उज्ज्वला योजना

"स्वच्छ भारत बेहतर जीवन"

केंद्र सरकार ने "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ 1 मई 2016 को "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" का शुभारंभ किया। यह योजना आज धुआंरहित ग्रामीण भारत के सपने को साकार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 88 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने रिफिल लिया है। रिफिल लेने वाले लाभार्थी 2017-18 में 3 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 6 करोड़, 2019-20 में 6.5 करोड़, 2020-21 में 8 करोड़, 2021-22 में 8.05 करोड़ और 2022-23 में 8.41 करोड़ हो गए हैं। लाभार्थियों द्वारा लिया गया कुल रिफिल, जो 2018-19 में 16 करोड़ था, वह 2022-23 में बढ़कर 35 करोड़ हो गया है। सरकार ने सितंबर 2023 में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है।

श्रीमती शोभा विजेन्द्र

समाज सेविका या संस्थापक, संपूर्णा

उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ने गरीब महिलाओं की रसोई तक गैस और चूल्हा पहुंचाने का काम किया है। इस योजना का लाभ देश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाली उन महिलाओं को भी मिला है जो खाना बनाने के लिए जंगलों से लकड़ियां बीन कर लाती थीं। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की आंखों की रोशनी बढ़ी है और सांस की बीमारियों में कमी आई है। प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की बहनों के लिए घर-घर में 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण करा कर उन्हें सम्मान जनक जिंदगी दी है।

सबका साथ
सबका विकास
सबका विश्वास सबका प्रयास

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'। इन आठ शब्दों में मानो भारत का संपूर्ण संविधान और उसकी आत्मा का सार निहित है। ये आठ शब्द संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण हैं। प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा ही विश्वास है। सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ चलना है,तरक्की सबकी होनी है, इसलिए प्रयास भी सबको करना है। वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो 'सबका साथ,सबका विकास' का नारा दिया, वो आज 'सबका साथ, सबका विकास' से आगे,'सबका विश्वास और सबका प्रयास' तक पहुंच गया है।

स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज

आचार्य महामंडलेश्वर, आनंदपीठाधीश्वर

स्वामी जी का मानना है कि मोदी जी ने न केवल 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दिया है, बल्कि उसे चरितार्थ करके भी दिखाया है। उनकी योजनाओं का लाभ आज समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 4 लाख से अधिक पक्के मकान बने हैं। स्वच्छ भारत योजना के तहत 11 करोड़ 68 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है।

मोदी यानी मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया

सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास की अवधारणा वास्तव मे नरेंद्र मोदी जी के शासन मॉडल की आधारशिला भी यही है। यह उस मिथक को भी तोड़ता है,जिसमें कभी कहा जाता था कि किसी जाति, समुदाय, धर्म, वर्ग, गांव, शहर अथवा क्षेत्र का विकास दूसरे की कीमत पर होता है। परंतु मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी क्षेत्र का विकास, किसी व्यक्ति का उत्थान तथा किसी देश की प्रगति सर्वजन को समाहित करके ही संभव है। आज किसान सम्मान, आवास, जनधन और उज्ज्वला जैसी तमाम योजनाओं का लाभ देश की 140 करोड़ जनता बिना भेदभाव के उठा रही है।

"सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार, विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है।"

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री ठाकुर अनूप सिंह

संस्थापक, मार्ग ईआरपी लि.

श्री ठाकुर अनूप सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी जो सोचते हैं, वो करते हैं। बात व्यापार की हो या बाजार की, बात किसान की हो या कामगार की, सभी के लिए पारदर्शीता से काम हो रहा है। आपका कहना है कि छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनके हित का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी जी के शासन काल में विकास की बहार है,लेकिन व्यापारियों को कंप्यूटराइज करना और सॉफ्टवेयर पर छूट देना आवश्यक है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

धन के लिए अतृप्त लालसा और कभी ना खत्म होने वाली तृष्णा ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है,जिससे चिंतित प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से "भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान" का शुभारम्भ किया। देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। भ्रष्टाचार की दीमक से देश को मुक्त करना है।स्वच्छता अभियान की तरह ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार करना है। हर देशवासी को इस प्रयास में अपना हाथ बंटाना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार उन्मूलन के बिना एक समर्थ राष्ट्र की कल्पना असंभव है।

“ना खाऊंगा न खाने दूंगा”

“अगर सपनों को सिद्ध करना है और संकल्प को पार करना है,तो हमें तीन बुराइयों से लड़ना होगा। पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, दूसरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है और तीसरी लड़ाई तुष्टिकरण के खिलाफ है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोंच लिया है,लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोंच लिया है। इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ के रखा है, इसने लोगों का हक छीना है। तीसरी बुराई तुष्टिकरण की है। इस तुष्टिकरण ने देश की मूलभूत चिंतन को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं। तहस-नहस कर दिया है। इसलिए हमें इन बुराइयों...भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के साथ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री अन्ना हजारे

समाज सेवी

श्री अन्ना हजारे जी को अप्रैल 2012 में केवल 5 दिनों में जनयुद्ध कर क्रांति करने वाले तथा आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के जंतरमंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-आंदोलन कर तत्कालीन सरकार को झुका देने वाले अन्ना जी का कहना है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जो प्रहार किया है,उससे बहुत बदलाव आया है। लेकिन अभी ये बदलाव सिर्फ दिल्ली के मंत्रालयों में नजर आ रहा है। नीचे के लोगों को इससे अभी जूझना पड़ रहा है। इस दिशा में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है।

विश्व योग दिवस (आयुष)

योग भगाए रोग

"जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वही आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। इसलिए, आज हमें 'डेटा बेस्ड एविडेंसेस' का डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। 30 से अधिक देशों ने आयुर्वेद को एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी है। हमें दूसरे देशों में भी आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। भारत ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अपने योगदान और उपलब्धियों के माध्यम से विश्व के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।"

– गोवा में प्रधानमंत्री 11 दिसम्बर 2022

मानव जीवन में आयुर्वेद और आयुष का गहन महत्व रहा है। यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देखभाल की पद्धति है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव की सेवा कर रही इस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से 9 नवंबर 2014 को, भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। अपनी स्थापना के लगभग 9 वर्षों में आयुष मंत्रालय और भारत सरकार ने इसके एकीकृत विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आयुष शिक्षा, अनुसंधान और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में मंत्रालय का कार्य सराहनीय है।

डॉक्टर वल्लभभाई कथीरिया

पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार

डॉक्टर कथिरिया कहते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता देना सरकार का क्रांतिकारी कदम है। कोरोना काल में आयुर्वेदिक उपचार और सनातन संस्कृति में वर्णित उपाय कारगर सिद्ध हुए। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लोगों को इनके के लिए प्रेरित किया। आयुष आज रोजगार का अवसर उपलब्ध करा रहा है। आयुर्वेद सहित योग, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तक पहुंच चुकी हैं। साल 2025 तक आयुष का बाज़ार 70 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

वैद्यराज भरत देव मुरारी

वैद्य, आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल

वैद्यराज भरत देव मुरारी जी एक प्रसिद्ध आयुर्वेद रोग विशेषज्ञ हैं। आप पंचगव्य से कैंसर जैसे गंभीर और असाध्य रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करते हैं। वैद्यराज के अनुसार योग अपनाकर और जीवनशैली में परिवर्तन करके व्यक्ति शतायु हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने के लिए आप प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सराहना करते हैं और कहते हैं कि भारतीय शास्त्रों और वेद-पुराणों में आयुर्वेद चिकित्सा से सभी रोगों का उपचार वर्णित है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अब आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी कार्य करेंगे।

संस्कृत और संस्कृति

संस्कृत विश्व की सबसे विकसित और वैज्ञानिक भाषा है। इसमें असीमित ज्ञान का भंडार है। संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है, जिसमें 45 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। संस्कृत को देववाणी अथवा सुरभारती भी कहा जाता है। इस भाषा के वर्ण ऋषि-मुनियों द्वारा गहरे ध्यान के बाद इस दुनिया को प्राप्त हुए। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है।

श्री रमेश भाई ओझा

आध्यात्मिक गुरु

आध्यात्मिक गुरु श्री रमेश भाई ओझा जी राजनीति और धर्म को एक ही सिक्के का दो पहलू मानते हैं और कहते हैं कि दोनों मिलकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका कहना है कि मोदी जी के शासनकाल में राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, सनातन धर्म के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। इसका उदाहरण राम मंदिर है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में वचन दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, तो पूरी प्रजातांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वोच्च अदालत के आदेश पर मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें रामलला विराजमान हुए और करोड़ों सनातनियों में उत्साह का संचार हुआ।

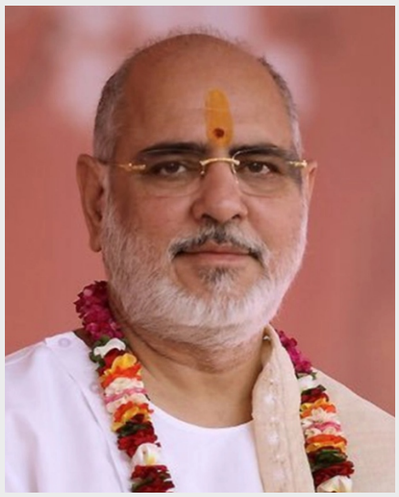

“मन और आत्मा का विस्तार है संस्कृति”

"हमें गर्व है कि विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है,जो हमारी विरासत का प्रतीक है। यह ज़ान-विज़ान तथा संस्कृति एवं संस्कार की भाषा है।"

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

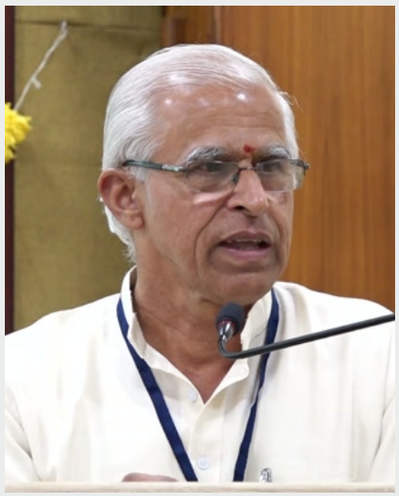

श्री दिनेश कामत

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, संस्कृत भारती

श्री दिनेश कामत जी का कहना है कि विगत 70 साल में भारत की शिक्षा पाश्चात्य दिशा में जा रही थी,लेकिन पहली बार इसका दिशा परिवर्तन हुआ है। मातृ भाषा पर जोर देने का जो कार्य आरंभ हुआ है, उसका संस्कृत भारती समर्थन करती है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान है। लेकिन संस्कृत भारती चाहती है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक संस्कृत अवश्य पढ़ाया जाए। विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए।

हिंदुत्व

भारत की सबसे बड़ी शक्ति हिन्दू धर्म और हिंदुत्व रहा है। यही कारण है कि शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिन्दुत्ववादी संगठनों की ओर से हिन्दू राष्ट्र की मांग लंबे समय से चली आ रही है। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक धर्मसभा में भी देशभर के धर्मगुरुओं ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूज्यपादों ने यह उम्मीद भी जताई कि भारत के हिन्दू राष्ट्र बनते ही 15 दूसरे देश भी स्वयं को हिन्दू राष्ट्र घोषित करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो हिन्दू राष्ट्र की मांग और ज्यादा बढ़ी है।

"हिन्दुत्व एक धर्म नहीं, जीवनशैली है"

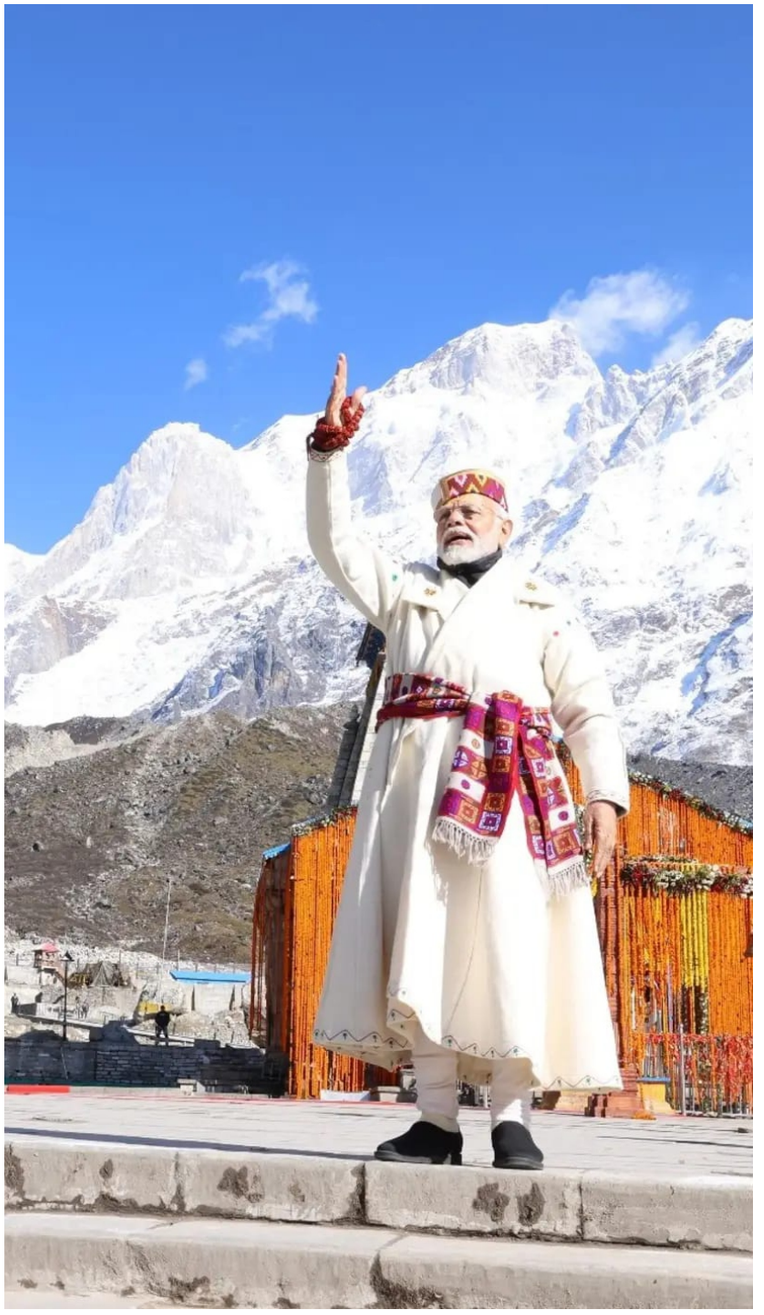

"हिन्दुत्व एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। प्रधानमंत्री ने ये बातें 17 अप्रैल 2015 को अपने कनाडा दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने वैज्ञानिक जीवन पद्धति के जरिए वन्यजीवों समेत प्रकृति के लाभ के लिए काम किया है। यह जीवन की छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखा सकता है।"

– कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

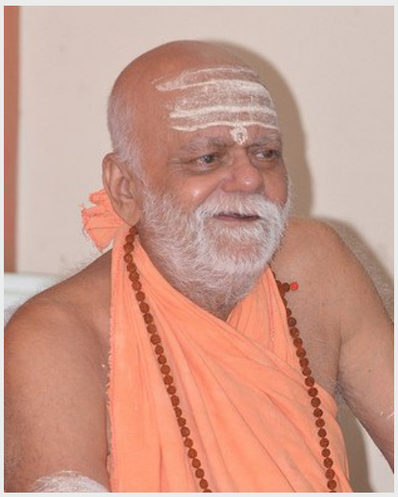

जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती

शंकराचार्य, गोवर्धन पीठ

ओडिशा प्रांत के पुरी स्थित गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा हेतु सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर लाने का कार्य किया है। स्वामीजी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की भावना और नियत पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन उनसे अपेक्षा है कि भारत को वैदिक संस्कृति के अनुरूप परिभाषित और क्रियान्वित करने का कार्य करके ना केवल भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, बल्कि पूरे विश्व के हित का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।

जनजाति कल्याण

प्रधानमंत्री जी द्वारा वनवासियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को वनवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। देशभर में आदिवासी संग्रहालय खोले गए हैं। जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। गोबरधन (गाय के गोबर का उपयोग), वनधन योजना (वन उपज) संचालित हैं। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाए गए, पीएम आवास जैसी योजनाएं सूचीबद्ध की गईं। प्रसव के बाद माताओं के कल्याण के लिए मातृत्व वंदना योजना, ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई। मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ एकलव्य विद्यालय भी खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जनजातियों के योगदान की सराहना की और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को याद किया।

भगवान बिरसा मुंडा

PARLIAMENT LIBRARY

“वनवासियों का बदला जीवन”

“मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। 15 नवंबर की ये तारीख,भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को **जनजातीय गौरव दिवस** के रूप में घोषित करने का अवसर मिला। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आज़ादी के महानायक नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के ‘पंच प्राणों’ की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री अतुल जोग

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वनवासी कल्याण आश्रम

संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री जोग जी लंबे समय से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। “नमो इम्पैक्ट” से बातचीत में श्री जोग ने कहा कि सरकार जो वनधन योजना लाई है, वो अच्छा प्रयास है। लेकिन कानून में संशोधन करके धर्म परिवर्तन करने वाले वनवासियों को जनजातीय सूची से बाहर करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि वनवासी समाज के धर्म, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हो सके।

स्मार्ट सिटी मिशन

"स्मार्ट सिटी मिशन" का शुभारम्भ 25 जून, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा हुआ। मिशन का लक्ष्य शहरों के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत रूप से विकास करना तथा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित शहरों में जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, यातायात सुविधा, आवास, सुरक्षा तथा डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस मिशन के अंतर्गत अबतक चुने गए 100 शहरों में 46,374.24 करोड़ रुपये की लागत से 4,382 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया है। 14 शहरों में 2020 और 2021 में 116 करोड़ रुपये की लागत वाली 30 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है।

"देश में रेल आधुनिक हो रही है,तो वंदे भारत ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही हैं,तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“शहरों का हो रहा है चौतरफा विकास”

“नए भारत का निर्माण”

“शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और शहरी केंद्रों को विकास इंजन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर यह 25-30 साल पहले किया गया होता तो आज इसके अच्छे परिणाम होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।”

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

श्री मनोज परिदा

पूर्व सलाहकार, प्रशासक – चंडीगढ़

श्री मनोज परिदा जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को स्मार्ट बनाने का जो मंत्र दिया है,उसे यदि ठीक से लागू किया जाए,तो शहरों का कायाकल्प हो सकता है। देश को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेज गति से कार्य हो रहे हैं। शहरों में विभिन्न विकास परियोजनाएं युद्ध स्तर पर संचालित हैं। चंडीगढ़ भी उन्हीं में से एक है। यहां इस वक्त एक अत्याधुनिक शहर की सभी सुविधाएं हैं। यह शहर हर क्षेत्र में उत्कृष्ट है।

ब्रिटिशकालीन कानूनों से मुक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुपयोगी कानूनों से मुक्ति का अभियान भी चलाया है। अभियान के अंतर्गत शासन और व्यापार में सरलता हेतु 2000 से अधिक नियमों और कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने 25000 से अधिक शर्तों को भी समाप्त कर दिया है। इनमें कई कानून और शर्त, तो ब्रिटिश राज के समय से बने हुए थे, जो नागरिकों के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे थे। मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाण पत्र सत्यापित कराने की प्रथा और भर्ती में साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

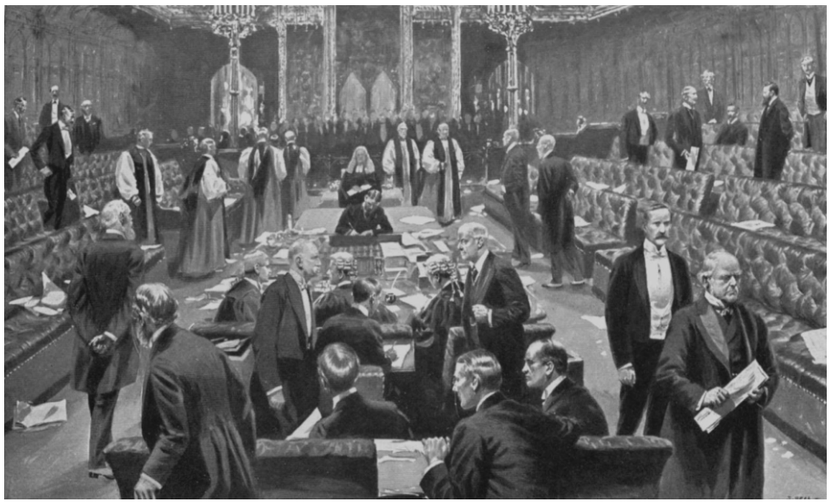

"उन दिनों जब मैं चुनाव प्रचार किया करता था तब दिल्ली में मुझे व्यापारियों ने घेर लिया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं हर दिन एक एक कानून खत्म करूंगा। जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए लेकिन जहां जरूरत नहीं हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए।"
-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

"अनावश्यक कानून खत्म लोगों को राहत"

श्री शशांक देव सुधी

एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री शशांक देव सुधी कहते हैं कि अनावश्यक तथा अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने का मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। सरकार के इस निर्णय का लाभ आम लोगों को मिलना तय है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अब तक सैंकड़ों ब्रिटिशकालीन कानूनों और प्रावधानों को हटाया गया है। शशांक जी सभी नियम और कानून को आज के परिपेक्ष में फिर से लिखने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

"मैं लालकिले से आपकी मदद मांगने आया हूं,मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आजादी के अमृतकाल में 2047 में,जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने हमें फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने के सबसे बड़े स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल हैं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान,पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

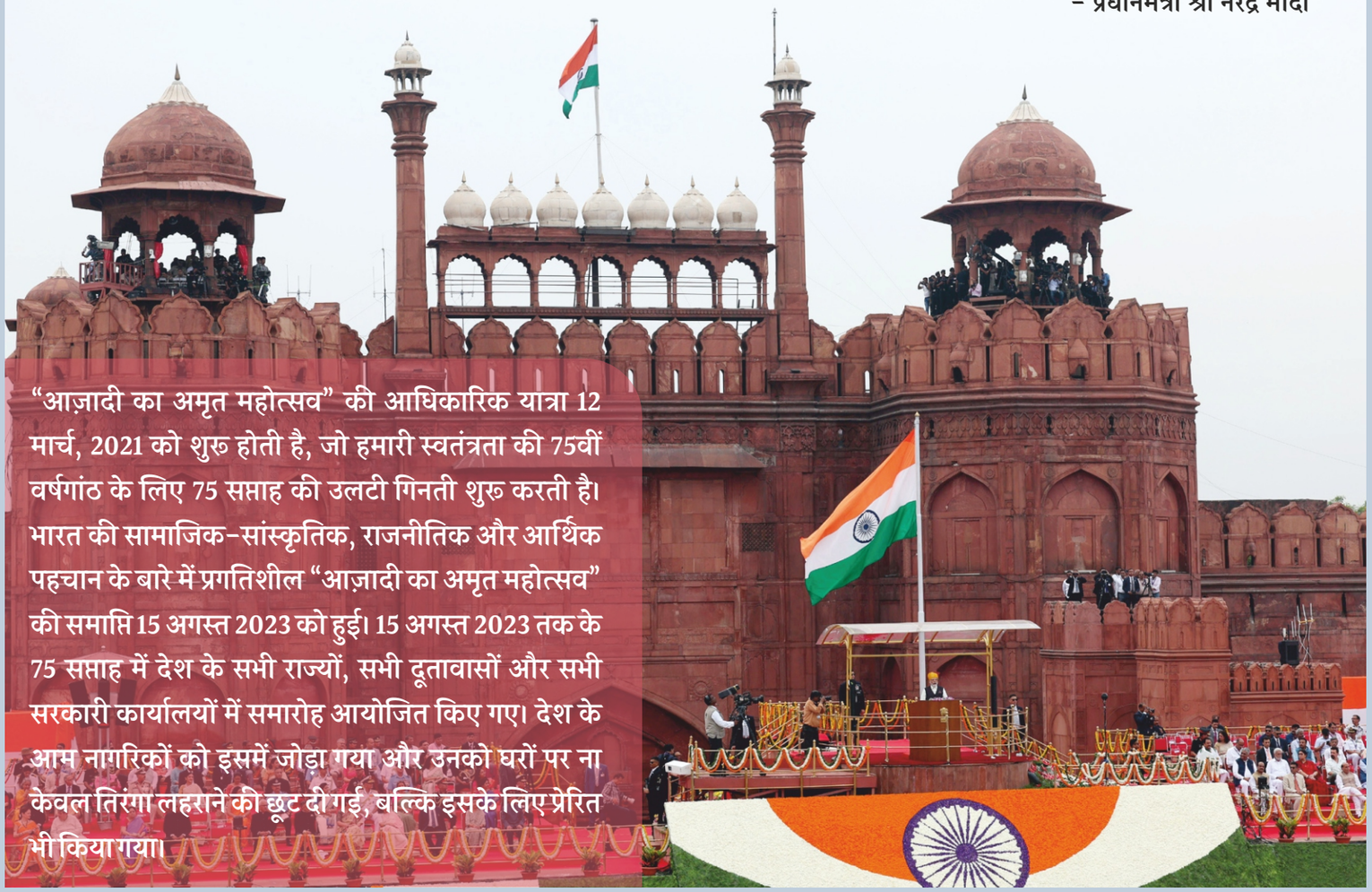

"आज़ादी का अमृत महोत्सव" की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू होती है, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उलटी गिनती शुरू करती है। भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील "आज़ादी का अमृत महोत्सव" की समाप्ति 15 अगस्त 2023 को हुई। 15 अगस्त 2023 तक के 75 सप्ताह में देश के सभी राज्यों, सभी दूतावासों और सभी सरकारी कार्यालयों में समारोह आयोजित किए गए। देश के आम नागरिकों को इसमें जोड़ा गया और उनको घरों पर ना केवल तिरंगा लहराने की छूट दी गई, बल्कि इसके लिए प्रेरित भी किया गया।

"अमृत काल सोते समय सपने देखने के लिए नहीं है, बल्कि सोच-समझकर अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए है। आने वाले 25 वर्ष अत्यंत परिश्रम, त्याग और तपस्या के कालखंड हैं। 25 वर्ष की यह अवधि सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो खोया है उसे वापस पाने के लिए है।"

-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

हर घर तिरंगा लहराया
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया

आजादी हमें 1000 साल की गुलामी और लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली है। अब देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इसे संभाल कर रखे। आदरणीय मोदी जी के कारण हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर असली आजादी का अनुभव कर पा रहे हैं।

- श्री जगदीश राय गोयल, चेयरमैन

आजादी का अमृत महोत्सव किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिए नहीं है। यह पूरे भारतवर्ष के लिए है। यह सभी भारतवासियों के दिल की आवाज है।

देखकर रंग तिरंगे का मेरी हर उमंग जागी है
हम नाचें-गाएं झूम कर झूमे,क्योंकि आज जश्न-ए-आजादी है।

- श्री राजेंद्र अग्रवाल, प्रधान

मेरी माटी मेरा देश

माँ भारती के वीर-वीरांगनाओं को सम्मान ज़ापित करने के उद्देश्य से 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान का शुभारम्भ 9 अगस्त 2023 को हुआ। स्वाधीनता दिवस और आजादी के अमृत वर्ष में आयोजित अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और मातृभूमि के प्रति कृतज़ता ज़ापित करना था। अभियान के अंतर्गत देशभर के सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में शिलालेखों का लोकार्पण और अमृत कलश यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए 'पंच प्रण' के प्रति हर देशवासी संकल्पबद्ध दिखे। वसुधा वंदन करते हुए पौधारोपण किया जा रहा है। तमाम पंचायतों, निकायों, प्रखण्डों, जिला मुख्यालयों और प्रदेशों की राजधानियों से होते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कलश संग्रहीत किए गए। कलशों में लाई गई मिट्टी और पौधों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास 'अमृत वाटिका' बनाई जा रही है।

'मिट्टी को नमन, वीरों का वन्दन'

"देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर-वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान शुरू हुआ। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभियान के दौरान 'अमृत कलश यात्रा' निकाली जाएगी, जो देश के विभिन्न कोनों और गांवों से 7500 कलशों में मिट्टी और पौधे लेकर दिल्ली पहुंचेगी। इन कलशों में ले जाई जा रही मिट्टी और पौधों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास 'अमृत वाटिका' बनाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश' अभियान में हिस्सा लेकर हम इन 'पंच प्राणों' को पूरा करने की शपथ भी लेंगे।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

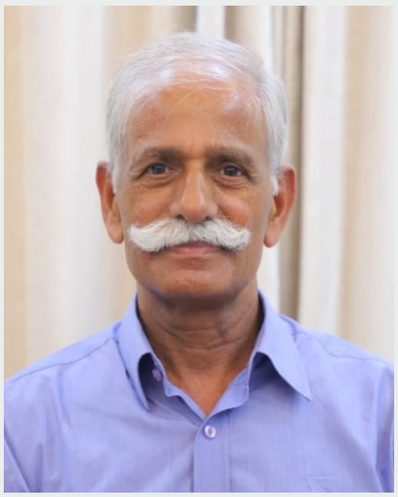

मेजर जनरल विजय पाल (सेवानिवृत)

युद्ध सेवा मेडल अलंकृत

युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत सेवानिवृत्त मेजर जनरल विजय पाल जी कहते हैं कि 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इसका उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीर-वीरांगनाओं का सम्मान करना है,जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इससे देश के आम नागरिकों के हृदय में सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत होगा। केंद्र सरकार ने सैनिकों को वह सम्मान दिया है,जिसके वह हकदार हैं। सैनिकों को 'वन रैंक वन पेंशन' का लाभ भी मिल रहा है। सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों के परिवार का ध्यान रखना सामाज का दायित्व है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

(उद्यमी भारत कार्यक्रम)

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रति प्रतिबद्ध है। कारोबारियों को केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। 2025 से 2027 तक सरकार के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए, इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की आवश्यकता है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रिय बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

"भारत ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 140 करोड़ से अधिक नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है। भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे एमएसएमई सेक्टर, आपको भी जाता है। ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत इकोनॉमिक पॉवरहाउस बन गया है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

“भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एमएसएमई”

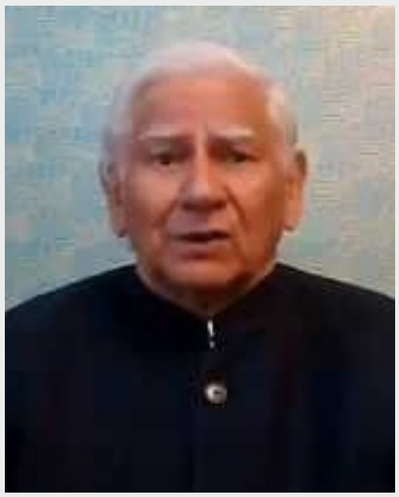

स्व. श्री सुदर्शन सरीन

पूर्व अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती

उद्योगपति और आधुनिक भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक श्री सुदर्शन सरीन जी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत का सपना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ही पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो इस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से रोजगार भी बढ़ सकता है और देश आत्मनिर्भर भी हो सकता है। सरकार इस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की समस्याओं का निराकरण करे, वित्तीय संकट को दूर करे, उन्हें प्रशिक्षण दे और इन्स्पेक्टर राज को समाप्त करे।

नमो impact राष्ट्र प्रथम

स्वामी चिदानंद सरस्वती जी

अतिथियों का स्वागत

श्री आरिफ मो. खान, राज्यपाल

नमो इम्पैक्ट
राष्ट्र प्रथम
कॉफी टेबल बुक
विमोचन समारोह

दीप प्रज्ज्वलन

नमो इंपैक्ट पुस्तक का विमोचन

प्रो. जगदीश मुखी, पूर्व राज्यपाल

मंचासीन मुख्य अतीथि

21 अक्टूबर 2023
प्रधानमंत्री सभागार तीन मूर्ति
नई दिल्ली, भारत

अतुल सिंघल, संपादक

अतिथियों का सम्मान

टीम नमो इम्पैक्ट

जस्टिस पंकज मित्तल, सुप्रीम कोर्ट

डॉ नंद किशोर गर्ग, कुलाधिपति

प्रधानमंत्री सभागार

राष्ट्रगान

सम्मान: श्री कुमार दिलीप पाठक

अधिवक्ता श्री शशांक देव सुधी

आयोजकगण

अध्यक्षता: सांसद श्री नरेश बंसल

नमो
impact

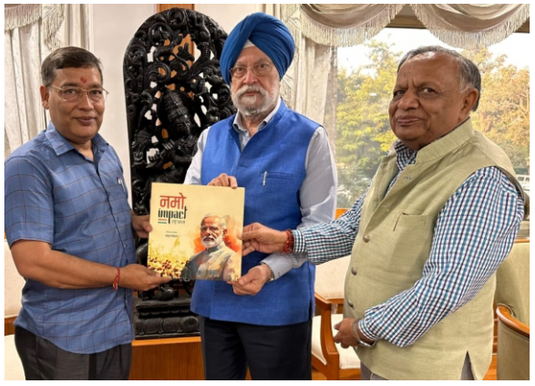
नमो
impact

नमो
impact

नमो
impact

नमो
impact

नमो
impact

'नमो इम्पैक्ट कॉफी टेबल बुक' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर आधारित साक्षात्कारों का एक संकलन है। यह साक्षात्कार पिछले 7 वर्षों के दौरान यूट्यूब सहित अलग-अलग टीवी चैनलों पर प्रसारित हुए हैं। बुक में केंद्र सरकार की नीतियों का विस्तृत वर्णन तथा निष्पक्ष विश्लेषण है। इसमें साक्षात्कार देने वाले विशेषज्ञ अतिथियों का सरकार की नीतियों के प्रति विचार और सुझाव हैं। यह जीवंत पुस्तक केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा परियोजनाओं को प्रदर्शित करती है। यह सभी के लिए जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। यह शुरू से अंत तक पढ़ी जाने वाली है। यह बुजुर्गों, वयस्कों और बच्चों के बीच भी रुचिकर है।

हरियाणा के चरखी दादरी से संबंध रखने वाले अतुल सिंघल जी का जन्म प्रोफेसर श्री सुरेश चंद सिंघल और श्रीमती उषा सिंघल के घर हुआ। पिताश्री प्रो. सिंघल समाजसेवा को समर्पित हैं और हरियाणा प्रान्त के गौसेवा प्रमुख सहित कई दायित्वों का निर्वहन किया है। अतुल जी का टेलीविजन की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। पत्रकारिता विषय में स्नात्कोत्तर की उपाधि प्राप्त कर आपने कई टीवी चैनलों में वरिष्ठ पदों पर काम किया और अनेक महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण खबरें की हैं,जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल जगत की खबरें शामिल हैं। आप लंबे समय तक असम एवं नागालैंड के माननीय राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। माता-पिता की प्रेरणा से समाजसेवा में आपकी गहरी रुचि है। आपने कैंसर के प्रति जागरूकता, इसकी रोकथाम और उपचार को सेवा का माध्यम बनाया है। लंबे समय से एक पंचगव्य आधारित आयुर्वेदिक कैसंर अस्पताल की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। महाराजा अग्रसेन जी के कुल में जन्म लेने और भगवान श्रीराम का वंशज होने पर आपको गर्व है।

नमो इम्पेक्ट के यूट्यूब
चैनल को सुनने के लिए स्कैन करें

सामाजिक भागीदार

OM LOGISTICS LTD.
Making Business Simple

LOHIA

MOTIF
ELECTRIC

9 789385 830228

मूल्य: ₹ 5000/- $ 100/- £ 80/-